रजिस्ट्री स. डी (डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D. (D N)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 7, 1987/माघ 18, 1908
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 7, 1987/MAGHA 18, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1986

आयकर

का. आ. 307 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, दिनांक 7-1-1986 को अपनी अधिसूचना सं. 6558 की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है । क्रम सं. 13 के सामने कालम 1, 2 और 3 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी :—

अनुसूची

क्रम सं.	आयकर आयुक्त	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
13	कोचीन	कोचीन	1. आयकर परिमंडल-I अर्नाकुलम 2. आयकर परिमंडल-II अर्नाकुलम 3. वेतन परिमंडल, अर्नाकुलम 4. आयकर परिमंडल, मातनचेरी 5. आयकर परिमंडल, आलवाई 6. आयकर परिमंडल-I त्रिचूर 7. आयकर परिमंडल-II, त्रिचूर 8. आयकर परिमंडल, पालघाट 9. आयकर परिमंडल-I, कालीकट 10. आयकर परिमंडल-II, कालीकट

1	2	3	4
		11. आयकर	परिमंडल, कन्नानोर
		12. आयकर	परिमंडल, कसारगोड़
		13. निरीक्षी आयुक्त, कोचीन	सहायक निर्धारण,
		14. निरीक्षी आयुक्त	सहायक (निर्धारण) त्रिचूर
		15. गैर आवासी	परिमंडल, कोचीन

यह अधिसूचना 14-8-1986 से प्रभावी होगी ।

[सं. 6867 (फा. सं. 187/10/85-आ.क. नि. I)]

के. के. त्रिपाठी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Central Board of Direct Taxes

New Delhi, the 14th August, 1986

(INCOME-TAX)

S. O. 307 :— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes makes the following amendment to the Schedule to its notification No. 6558 dated 7-1-1986. Entries in column 1, 2 & 3 against serial No. 13 are substituted as under :—

SCHEDULE

Sl. No.	Commissioner of Income-Tax	Headquarters	Jurisdiction
1	2	3	4
13.	Cochin	Cochin.	1. Income-tax Circle-I, Ernakulam.
			2. Income-tax Circle-II, Ernakulam.
			3. Salary Circle, Ernakulam.
			4. Income-tax Circle, Mattancherry.
			5. Income-tax Circle, Alwaye.
			6. Income-tax Circle-I, Trichur.
			7. Income-tax Circle-II, Trichur.
			8. Income-tax Circle, Palghat.
			9. Income-tax Circle-I, Calicut.
			10. Income-tax Circle, II, Calicut.
			11. Income-tax Circle, Cannanore.
			12. Income-tax Circle, Kasargod.
			13. I.A.C. (Asstt.), Cochin.
			14. I.A.C.(Asst)., Trichur.
			15. Non-resident Circle, Cochin.

This Notification takes effect from 14-8-1986.

[No. 6867 (F. No. 187/10/85-IT(AI)]

K.K TRIPATHI, Dy. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1987

आदेश

का. आ. 308—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए रंगलेप तथा संबंध उत्पादों को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 2656, तारीख 2 अगस्त, 1986 के अधीन भारत के राजपत्र भाग-2, खंड-3, उपखंड-(ii), तारीख 26 जुलाई, 1986 में प्रकाशित किए गए थे ;

और जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी उन व्यक्तियों से उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 11-8-1986 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारूप प्रस्ताव पर जनता से जो आक्षेप या सुझाव प्राप्त हुए थे उन पर विचार कर लिया गया है ;

अतः निर्यात (क्वालिटी नयंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्यात निरीक्षण परिषद के परामर्श करने के पश्चात अपनी यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है :—

(i) यह अधिसूचित करती है कि रंगलेप तथा संबंध उत्पाद निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे ;

(क) सुसंगत भारतीय मानक या अन्य राष्ट्रीय मानकों, या निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकायों के मानकों को मान्यता देती है ;

(ii) उत्पादों के परिशिष्ट-I में दी गयी न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति करने के अधीन रहते हुए संविदात्मक विनिर्देशों को रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है।

(iii) परिशिष्ट-2 में दिए गए रंगलेप तथा सबद्ध उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1987 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जो ऐसे रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों को उनके निर्यात से पूर्व लागू होगा।

(iv) अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में ऐसे रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों के निर्यात को प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित अधिकरण द्वारा निर्यात के लिए जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि ऐसे रंगलेप तथा सम्बद्ध उत्पादों का मानक विनिर्देशों और अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार सम्यक रूप से निरीक्षण कर लिया गया है।

2. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को समुद्र, भूमि वायु, मार्ग द्वारा रंगलेप तथा सम्बद्ध उत्पादों के ऐसे सदभावी व्यापार के नमूनों को लागू नहीं होगी जिनका पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 500 रु. से अधिक नहीं है।

3. इस आदेश में :—

(i) "परिशिष्ट" से इस आदेश का परिशिष्ट अभिप्रेत है।

(ii) "रंगलेप तथा संबद्ध उत्पाद" से इस आदेश की सारणी-1 और सारणी-2 में दी गयी मदें अभिप्रेत हैं।

4. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

सारणी- 1

1. संश्लिष्ट इनेमल।
2. उष्मारोधी वार्निश (वायु शुष्कन बिटुमन प्रकार के)
3. संश्लिष्ट वार्निश, फिनिशिंग (सामान्य प्रयोजन के लिए)।
4. इमल्शन रंगलेप (प्लास्टिक ऐक्रिलिक इमल्शन)।

सारणी-2

1. सभी प्रकार के तैयार मिश्रित रंगलेप तथा इनेमल जिनके अंतर्गत संश्लिष्ट इनेमल के सिवाय प्राइमर, फिलर, अंडर कोटिंग तथा फिनिशिंग हैं।
2. संश्लिष्ट वार्निश फिनिशिंग (सामान्य प्रयोजन के लिए) तथा उष्मारोधी वार्निश (वायु शुष्कन, बिटुमन प्रकार के) के सिवाय सभी प्रकार के वार्निश प्राकृतिक लाख या संश्लिष्ट लाख या दोनों से बनाए गए।
3. प्लास्टिक तथा ऐक्रिलिक के सिवाय सभी प्रकार के इमल्शन रंगलेप।
4. फिलर, प्राइमर या सरफेसर सहित, नाइट्रोसेल्युलोस प्रलाक्ष, सादी या वर्णकित।
5. पेस्ट रंगलेप तथा पेस्ट डिस्टेम्पर।
6. सूखे डिस्टेम्पर, चूने के रंग तथा सीमेंट रंग।
7. सीमेंट रंगलेप।
8. रंगलेप को पतला करने वाले।
9. रंगलेप के लिए संश्लिष्ट लाख।
10. रंगलेप के लिए संसाधित तेल और रंगलेप के लिए शुष्कन या अर्धशुष्कन तेल।
11. विटुमिनियस कोटिंग।
12. एल्युमिनियम पेस्ट।

परिशिष्ट—1

न्यूनतम अपेक्षाएं.

1. सामान्य अपेक्षाएं :

1.1 प्रत्येक प्राइमरी डिब्बे को निम्नलिखित से चिन्हित किया जाएगा :—

(क) सामग्री का नाम और श्रेणी।

(ख) विनिर्माता का नाम और/या व्यापार चिन्ह।

(ग) कारखाना कोड, यदि विनिर्माता की एक से अधिक विनिर्माण एकक हैं।

(घ) सामग्री की मात्रा।

(ङ) विनिर्माण का बैच।

1.2 पैक में प्राइमरी डिब्बे इस तरह से पैक किए जाएंगे जिससे उनमें आपस में टकराव न हो।

1.3 डिब्बों की रिसाव परख और सीवन क्षमता की अपेक्षाएं ऐसी होंगी जो विनिर्माता द्वारा अधिकथित की जाएं।

1.4 प्रयुक्त डिब्बों (बैरल) या लकड़ी की पेटियों/गत्तेदार डिब्बों का जिनमें प्राइमरी डिब्बे पैक किए जाएंगे फिनिश अच्छी होगी और जोखिम सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे।

1.5 पैकने की पद्धति उत्पाद की ज्वलनशील प्रकृति डिब्बे की ऊर्ध्वाधरता और अन्य ऐसे सुसंगत पहलुओं के बारे में उठाई-धराई निर्देश विशेषतः अंतराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत साकेतिक कोड में पैक के बाहरी और प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे।

2. परीक्षण :

2.1 निर्यात के लिए लाट पर निम्न प्रकार परीक्षण लागू होगा :—

सारणी-1 की मदों के लिए-उपाबंध-(i) से (iv) के अनुसार।

सारणी–2 की मदों के लिए संविदात्मक अपेक्षाओं के अनुसार ।

टिप्पण : सारणी-2 की मदों की दशा में, सुसंगत राष्ट्रीय मानकों में की विशिष्टताओं के लिए विनिर्देश क्रेता की अपेक्षाओं के अनुसार संविदा में वर्णित किए जाएंगे ।

3. नमूना लेना :

3.1 नमूने के रूप में चयन किए जाने वाले डिब्बों की संख्या प्रति लाट वह होगी जो नीचे दी गयी है :—

नमूना लेने का माप व मान

लॉट आकार (डिब्बों की संख्या)	नमूना लेने के लिए चयन किए जाने वाले डिब्बों की संख्या
50 तक	3
51 से 100	4
101 से 200	5
201 से 300	6
301 से 400	7
401 से 800	8
801 और उससे अधिक	10

टिप्पण : नमूना लेने के प्रयोजन के लिए "लॉट", डिब्बों के नापों पर ध्यान दिए बिना, विशिष्ट कारखाना कोड वाले किसी विशिष्ट वर्ग के उत्पाद के विनिर्माण का प्रत्येक बैच होगा ।

3.2 परीक्षण नमूनों की तैयारी : लॉट से लिए गए प्रत्येक नमूने का भार के लिए, जहां कहीं लागू हो, प्रति दस लीटर अलग-अलग परीक्षण किया जाएगा और यदि विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पाया जाता है तो उसी लॉट में से लिए गए अलग-अलग नमूने की सामग्री को एक मिश्रित नमूना बनाने के लिए मिला लिया जाएगा । सभी अवशिष्ट विशेषताओं के लिए मिश्रित नमूनों का परीक्षण किया जाएगा।

3.3 परीक्षण की प्रणाली :—

परीक्षण की प्रणाली वह होगी जो निर्यात संविदा में विनिर्दिष्ट है । ऐसे विनिर्दिष्ट अनुबंध की अनुपस्थिति में परीक्षण की प्रणाली सुसंगत भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार होगी ।

उपाबंध—1

संश्लिष्ट इनेमल के लिए परीक्षण :—

1. प्रारम्भिक परीक्षण :—

ताजे खुले डिब्बों में सामग्री लिवरिंग, अस्थिरता और आदृढ़ स्थरण वाली नहीं होगी । विलोडित अवस्था पर श्रुश करने के लिए वह एक सार, चिकना और सामग्री उत्पाद बनाएगा । तथापि सामग्री को पतला करने के पश्चात् उसमें गाढ़ा छिड़काव होगा ।

2. फिनिश :—

जब पैनल पर विहित रूप में लगाया जाए तब फिनिश चिकनी और चमकदार होगी, कंकरीलेपन, रंग के अलगाव या अन्य कोई सतही अपूर्णता से मुक्त होगी ।

3. पिसाई की सफाई :—

ग्राईंडिंग गेज (हैगमेन) से जब परीक्षित किया जाएगा तब वह कम से कम 6 की रीडिंग देगा ।

4. सामग्री नीचे दी गई अपेक्षाओं के भी अनुरूप करेगी ।

क्रम सं.	विशेषताएं	अपेक्षाएं
1. (i)	शुष्कन समय	
	(क) सतह शुष्कन	अधिकतम 8 घंटे
	(ख) कठोर शुष्कन	अधिकतम 18 घंटे
	(ग) टैक मुक्त शुष्कन	अधिकतम 24 घंटे
(ii)	रंग	क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में (निकटतम मैच) हो
(iii)	30° सें. ग्रे. पर बी-4 फोर्ड कप में स्थानता	± 15 सैकंड विनिर्दिष्ट
(vi)	भार प्रति 10 लीटर	± 3 प्रतिशत विनिर्दिष्ट
(v)	प्रज्वलन ताप	30° सें. ग्रे. से कम नहीं
(vi)	खरोंच कठोरता परीक्षण	परीक्षण पास करना होगा
(vii)	लचीलापन और आसंजन परीक्षण	परीक्षण पास करना होगा
(viii)	अपखंडन परीक्षण	परीक्षण पास करना होगा

5. पक्के रंग के लिए परीक्षण :—

नमूनों को परीक्षण पास करना होगा ।

(खंड—3.3)

नोट : यह परीक्षण प्रत्येक परेषण पर करने की आवश्यकता नहीं है । प्रत्येक विनिर्माता सभी निरूपणों के लिए प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार यह परीक्षण करेगा ।

उपाबंध—2

उष्मारोधी वार्निश के लिए परीक्षण (वायु शुष्कन, बिटुमन प्रकार के) :

1. प्रारम्भिक परीक्षण :—

ताजे खुले डिब्बों में सामग्री गहरे भूरे से काले रंग, तरल अवस्था में, पपड़ी बनाने से मुक्त, बाह्य पदार्थों और अवसाद से मुक्त होगी । विलोड़ित किए जाने पर यह साफ, एकसार और संभागी मिश्रण होगी ।

2. कॉपर के साथ वार्निश की प्रक्रिया :—

जब परीक्षण किया जाए तब कॉपर का रंग नहीं बदलेगा ।

3. (क) 5000 वोल्ट/मिलीलीटर (न्यूनतम) कक्ष तापमान पर वायु में विद्युत क्षमता वोल्ट/मि. मी. में होगी ।

(ख) पानी में निमज्जन के पश्चात् विद्युत् क्षमता :—

सामग्री को 3000 वोल्ट/मि.मी. (न्यूनतम) पर परीक्षण पास करना होगा।

4. सामग्री नीचे दी गई अपेक्षाओं के भी अनुरूप होगी :—

क्रम सं.	विशेषताएं	अपेक्षाएं
(i)	भार प्रति 10 लीटर	±5 प्रतिशत विनिर्दिष्ट
(ii)	30° सें. ग्रे. पर बी-4 फोर्ड कप में स्थानता	±15 सैकेंड विनिर्दिष्ट
(iii)	शुष्कन समय	
	(क) कठोर शुष्कन	अधिकतम 6 घंटे
	(ख) टैक मुक्त शुष्कन	अधिकतम 24 घंटे
(iv)	प्रज्वलन ताप	30° सें. ग्रे. से कम नहीं
(v)	रंग	नमूने के अनुसार (निकतम मैच हो)
(vi)	नम्यता क्षमता की संगतता	100%
(vii)	अवाष्पशील पदार्थ %	±3% विनिर्दिष्ट
(viii)	खनिज तेल प्रतिरोध	परीक्षण पास करना होगा।
(ix)	उष्मा सह्यता परीक्षण	परीक्षण पास करना होगा।
(x)	लचीलापन तथा आसंजन परीक्षण	परीक्षण पास करना होगा।

उपाबंध—3

संश्लिष्ट वार्निश, फिनिशिंग के लिए परीक्षण (सामान्य प्रयोजन के लिए)

1. प्रारम्भिक परीक्षण :—ताजे खुले डिब्बों में सामग्री लिवरिंग या अस्थिरता के कोई भी चिन्ह नहीं दिखाएगी। सामग्री साफ पारदर्शी तथा अवसाद और पपड़ी से मुक्त होगी। इसके संघटकों को विडोलित किए जाने पर एक सार और समांगी बनाने के लिए तेजी से बिखेरा जाएगा।

2. फिनिश :—जब सामग्री विहित पैनल पर लगाई जाए तब फिनिश चिकनी और चमकदार होगी।

3. सामग्री नीचे दी गयी अपेक्षाओं के भी अनुरूप होगी :—

क्रम सं.	विशेषताएं	अपेक्षाएं
(1)	शुष्कन का समय	
	(क) सतह शुष्कन	छः घंटे (अधिकतम)
	(ख) कठोर शुष्कन	18 घंटे (अधिकतम)
	(ग) शुष्कन	24 घंटे (अधिकतम)
(2)	रंग	नमूने के अनुसार (निकटतम मैच हो)
(3)	प्रज्वलन ताप	30% सें. ग्रे. से कम नहीं
(4)	वाष्पशील पदार्थ %	60% अधिकतम
(5)	30° सें. ग्रे. पर स्थानता	1=3 स्टोक
(6)	अम्लमान	25.0 (अधिकतम)
(7)	भार प्रति 10 लीटर	±3 विनिर्दिष्ट
(8)	क्षार प्रतिरोध	परीक्षण पास करना होगा
(9)	अम्ल प्रतिरोध	परीक्षण पास करना होगा।
(10)	जल प्रतिरोध	परीक्षण पास करना होगा
(11)	खरोंच कठोरता परीक्षण	परीक्षण पास करना होगा
(12)	लचीलापन और आसंजन परीक्षण	परीक्षण पास करना होगा
(13)	अपखंडन परीक्षण	परीक्षण पास करना होगा

उपाबंध—4

इमलशन रंगलेप के लिए परीक्षण (प्लास्टिक/ऐक्रिलिक इमलशन)

1. प्रारम्भिक परीक्षण :—ताजे खुले डिब्बों में सामग्री ढेलों और पपड़ी से मुक्त होगी, अधिक स्थूरण केकन, कणिकायन, लिवरिंग या रंग पृथक्करण प्रदर्शित नहीं करेगी और चिकनी और एकसार अवस्था में निर्लेपन के साथ आसानी से बिखेरी जाएगी। यह घृणोत्पादक रंग से मुक्त होगी। पतला करने के पश्चात् ब्रश या छिड़काव या रोलर द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए गाढ़ापन, चिकना और एकसार होगा।

2. शुष्कन समय :—रंगलेप के सतह शुष्कन का समय 1 घंटा (अधिकतम) होगा तथा पुनः विलेपन का समय 4 घंटे (अधिकतम) होगा।

3. फिनिश :—जब विहित पैनल पर सामग्री को लगाया जाए तब फिल्म की फिनिश चिकनी होगी और अण्डे की सफेदी जैसी चमकदार होगी।

4. रंग :—विदेशी क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट मानक के लिए निकटतम मैच हो।

5. गीला अपघर्षण प्रतिरोध :—रंगलेप फिल्म को 4000 दोलन के लिए परीक्षण पास करना होगा।

6. भार प्रति 10 लिटर :—विनिर्दिष्ट भार प्रति 10 लिटर पर सह्यता ±15 प्रतिशत होगी।

7. हल्के से पक्का :—नमूने को परीक्षण पास करना होगा।

8. क्षार प्रतिरोध :—नमूने को परीक्षण पास करना होगा।

[फाइल सं. 6 (5)/85—ई आई एड ई पी]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 2nd February, 1987

ORDER

S.O. 308.—Whereas for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting paints and allied products to quality control and inspection prior to export, were published as required by Sub-rule (2) of Rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 2nd August, 1986, under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2656 dated the 2nd August, 1986;

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within 45 days of the publication of the said Order in Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 11-8-1986;

And whereas objections or suggestions have been received from the public on the said draft proposals, have been considered.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government, after consultation with the Export Inspection Council, being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India, hereby:—

(i) notifies that paints and allied products shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(ii) recognises—

(a) relevant Indian Standard or any other national standard; or standards of other bodies recognised by Export Inspection Council;

(b) Contractual specifications subject to the products satisfying the minimum requirements as set out in Appendix-I as the standard specifications for paints and allied products.

(iii) specifies the type of quality control and inspection in accordance with the Export of paints and allied products (Quality Control and Inspection) Rules, 1987 as set out in Appendix-II as the type of inspection which shall be applied to such paints and allied products prior to their export;

(iv) prohibits the export of such paints and allied products in the Course of international trade unless the same are accompanied by an inspection certificate for export issued by an Agency established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that such paints and allied products have been duly inspected in accordance with the standard specification and requirements of the Act.

2. Nothing in this Order shall apply to the export by sea, land or air of bonafide trade samples of paints and allied products not exceeding Rs. 500/- only in free on board value to the prospective.

3. In this Order:—

(i) 'Appendix' means an appendix to this order.

(ii) 'paints and allied products' means items given in Table-I and II to this order.

4. This order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

TABLE-I

1. Synthetic enamels.
2. Insulating varnishes (Air drying, Bitumen type).
3. Syenthotic varnishes, finishing (General purposes)
4. Emulsion paints, (Plastic/Acrylic emulsion).

TABLE-II

1. Ready-mixed paints and enamels of all types including primers, fillers under-coating and finishing except synthetic enamels.
2. Varnishes of all types (prepared from natural resin or or synthetic resins or both) except synthetic varnishes finishing (general purposes) and insulating varnishes (air drying, bitumen type).
3. Emulsion paints of all types except plastic and acrylic.
4. Nitrocellulose lacquers, clear or pigmented including filler, primers or surfacers.
5. Paste paints and paste distempers.
6. Dry distempers, limecolours and cement colours.
7. Cement paints.
8. Thinners for paints.
9. Synthetic resin for paints.
10. Processed oils for paints and drying or semidrying oils for paints.
11. Bituminous coatings.
12. Aluminium paste.

APPENDIX-I

MINIMUM REQUIREMENTS

1. GENERAL REQUIREMENTS

1.1 Each primary container shall be marked with the following—

(a) Name and description of the material;

(b) Name of the manufacturer and/or trade mark;

(c) Factory code when a manufacturer has more than one manufacturing unit;

(d) Quantity of the material;

(e) Batch of manufacture;

1.2 The primary containers in a pack shall be so packed as to avoid collisions amongst them.

1.3 The requirement of the leakpoofness and seam strength of containers shall be as laid down by the manufacturer.

1.4 The bulk conainers (barrels) or the wooden cases or corrugated boxes in which primary containers are packed shall be well finished and strong enough to withstand hazards.

1.5 Handling instructions preferably in internationally accepted symbolic codes in respect of method of slinging, inflammable nature of product, vertical position of container and such other relevant aspects shall be predominantly displayed on the outer packs.

2. TESTS

2.1 The tests which shall be applied against a lot for export shall be as below:—

For Table I items-As per Annexure (i) to (iv)

For Table II items-As per contractual requirements.

NOTE:—In the case of Table II items, specifications against the characteristics in the relevant National Standards are to be mentioned in the contract as per buyer's requirements.

3 SAMPLING

3.1 The number of containers to be selected as samples per lot shall be as given below :

SCALE OF SAMPLING

Lot size (Number of containers)	Number of containers to be selected for sampling
Upto 50	3
51 to 100	4
101 to 200	5
201 to 300	6
301 to 400	7
401 to 800	8
801 and above	10

NOTE : A 'lot' for the purpose of sampling shall be each batch of manufacture of the particular class of product bearing the particular factory code irrespective of the container sizes.

3.2 Preparation of test samples.—Each sample drawn from a lot shall be individually tested for weight per 10 litres where applicable and if found conforming to the specified standard. The material of individual samples drawn from the same lot shall be blended to make a composite sample. Tests for all remaining characteristics shall be conducted on the composite sample.

3.3 Methods of test.—Methods of tests shall be as stipulated in the export contract. In the absence of such specific stipulation methods of tests shall be as per the relevant Indian Standard Specifications.

ANNEURE I

Tests for Synthetic Enamels

1. Preliminary Examination.—The material in a freshly opened container shall not show livering, instability and hard settling. On stirring it shall form a uniformm, smooth and homogeneous product suitable for application by brushing. However, after thinning the material shall be of spraying consistency.

2. Finish.—When applied on a panel as prescribed, the finish shall be smooth and glossy free from grittings separation of colour or any other surface imperfection.

3. Fineness of Grind.—When tested with Grinding gauge (Hegman) it shall give a minimum reading of 6.

4. The material shall also comply with the requirements given below :

S. No.	Characteristics	Requirements
(i)	Drying time	
	(a) Surface dry	8 hours maximum
	(b) Hard dry	18 hours maximum
	(c) Tack free dry	24 hours maximum
(ii)	Colour	As specified by buyer (small be a close match)
(iii)	Viscosity in B-4 Ford Cup at 30°C	Specified ± 15 seconds
(iv)	Weight per 10 litres	Specified ± 3%
(v)	Flash point	Not below 30°C
(vi)	Scratch hardness test	To pass the test
(vii)	Flexibility and adhesion test	To pass the test
(viii)	Stripping test	To pass the test

5. Colour Fastness Test.—The sample shall pass the test (Clause 3.3)

Note : This test need not be done on every consignment. Each manufacturer shall carry out this test at least once in every six months for each formulation.

ANNEXURE II

Tests for Insulating Varnishes (Air Drying, Bitumen Type)

1. Preliminary Examination.—The material in a freshly opened container shall be dark brown to blackish in colour, liquid in state, free from skin formation, foreign matter and sediments. On stirring it shall become a smooth, uniform and homogeneous mixture.

2. Reaction of varnish with Copper.—The copper shall not change colour when tested.

3. (a) Electric strength in volts/mm. in air at room temperature 5000 volts/mm. (Minimum).

(b) Electric strength after immersion in water.—The material shall pas the test at 3000 volts/mm. (minimum)

4. The material shall also comply with the requirements given below :

Sl. No.	Characteristics	Requirements
(i)	Weight pre 10 litre	Specified ± 5%
(ii)	Viscosity in Ford Cup B-4 at 30°C	Specified ± 15 seconds
(iii)	Drying time	
	(a) Hard dry	6 hours maximum
	(b) Tack free dry	24 hours maximum
(iv)	Flash point	Not below 30°C
(v)	Colour	As per sample (shall be a close match)
(vi)	Compatibility of dilution ability	100%
(vii)	Non-volatile matter %	Specified ±3%
(viii)	Resistance to mineral oil	To pass the test (Clause 3)
(ix)	Thermal endurance test	To pass the test (clause 3)
(x)	Flexibility and adhesion test	To pass the test (clause 3)

ANNEXURE III

Tests for Synthetic Varnishes Finishing (General purposes)

1. Preliminary Examination.—The material in a freshly opened container shall show no sign of livering or instability. The material shall be clear, transparent and free from sediment and skin. On stirring its components shall be rapidly dispersed to be smooth and homogenous.

2. Finish.—When the material is applied on a prescribed panel, the finish shall be smooth and glossy.

3 The material shall also comply with the requirements given below :

S. No.	Characteristic	Requirement
(i)	Dryingtime	
	(a) Surface dry	6 hours (Maximum)
	(b) Hard dry	18 hours (Maximum)
	(c) Tack free dry	24 hours (Maximum)
(ii)	Colour	As per sample (shall be a close match)
(iii)	Flash point	Not below 30°C
(iv)	Volatile matter %	60% maximum
(v)	Viscosity at 30°C	1—3 stockes
(vi)	Acid value	25-0 (Maximum)
(vii)	Weight per 10 litres	Specified ± 3%
(viii)	Resistance to alkali	To pass the test
(ix)	Resistance to acid	To pass the test
(x)	Resistance to water	To pass the test
(xi)	Scratch hardness test	To pass the test
(xii)	Flexibility and adhesion test	To pass the text
(xiii)	Stripping test	To pass the test

ANNEXURE IV

Test for Emulsion Paints (Plastic/Acrylic Emulsion)

1. Preliminary Examination.—In a freshly opened container, the material shall be free from lumps and skin, shall not exhibit excessive settling caking, granulation, livering or colour separation and shall be easily dispersed with a stirrer to a smooth homogeneous state. It shall be free from offensive colour. The consistency shall be smooth and uniform suitable for applying by brushing or spraying or by roller after thinning.

2. Drying Time.—The paint shall have a surface drying time of 1 hour (Maximum) and recoating time of 4 hours (Maximum).

3. Finish.—When the material is applied on a prescribed panel the finish of the film shall be smooth and matter or of egg shell gloss.

4. Colour.—It shall be a close match to standard specified by the foreign buyer.

5. Resistance to wet abrasion.—The paint film shall pass the test for 4000 oscillations.

6. Weight per 10 litres.—The tolerance on the specified weight per 10 litres shall be ± 5%.

7. Wastness to light.—The sample shall pass the test.

8. Resistance to alkali.—The sample shall pass the test.

[F. No. 6(5)/85-EI&EP]

का. आ. 309.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम रंग लेप तथा संबद्ध उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1987 है।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का केन्द्रीय अधिनियम सं 22) अभिप्रेत है ;

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है।

(ग) "रंगलेप तथा संबद्ध उत्पाद" से अभिप्राय है :—

सारणी —1

(1) संश्लिष्ट इनेमल

(2) ऊष्मारोधी वार्निश (वायु शुष्कित, बिटुमन प्रकार)

(3) संश्लिष्ट वार्निश, फिनिशिंग (साधारण प्रयोजन)

(4) इम्लशन रंगलेप (प्लास्टिक/एक्रिलिक इमलशन)

सारणी—2

(1) संश्लिष्ट इनेमलों को छोड़कर सभी प्रकार के तयार मिश्रित रंगलेप तथा इनेमल जिनके अंतर्गत प्राइमर, फिलर, अंडरकोटिंग और फिनिशिंग भी है।

(2) संश्लिष्ट वार्निश फिनिशिंग (साधारण प्रयोजन) और ऊष्मारोधी वार्निशन (वायु शुष्कित, बिटुमन प्रकार) को छोड़कर सभी प्रकार की वार्निश प्राकृतिक राल या संश्लिष्ट राल या दोनों से तैयार की गई ।

(3) प्लास्टिक तथा एक्रिलिक को छोड़कर सभी प्रकार के इम्लशन रंगलेप।

(4) नाईट्रोसेल्यूलोज प्रलाक्ष स्वच्छ या रंग मिश्रित हुई जिसमें फिलर, प्राइमर या सरफेसर भी सम्मिलित हैं।

(5) पेस्ट रंगलेप तथा पेस्ट डिस्टेम्पर।

(6) सूखे डिस्टम्पर, चूर्ण रंग तथा सीमेंट रंग।

(7) सीमेंट रंगलेप।

(8) (रंगलेप में मिलाने के लिए विरलक ।

(9) रंगलेप के लिए संश्लिष्ट राल।

(10) रंगलेप के लिए संसाधित तेल या रंगलेप के लिए शुष्कन अर्धमा शुष्कन तेल।

(11) बिटुमन लेपित।

(12) एल्यूमिनियम पेस्ट।

(घ) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है :

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

3. निरीक्षण का आधार :—निर्यात के लिए आशयित रंगलेप तथा सम्बद्ध उत्पादों का निरीक्षण इस दृष्टि से किया जाएगा कि रंगलेप तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का केन्द्रीय अधिनियम 22) की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है :—

(क) यह सुनिश्चित करके कि उत्पाद अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट उत्पादन के दौरान अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करके विनिर्मित किया गया है; या

(ख) अनुसूची–III में विनिर्दिष्ट रीति से किए गए निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों के परेषण का निर्यात करने का आशय रखने वाला निर्यातकर्ता, निर्यात-संविदा या आदेश की एक प्रति के साथ संविदात्मक विनिर्देशों का ब्यौरा देते हुए अधिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा जिससे अधिकरण नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सकें ।

(2) इस प्रयोजन के लिए अधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञों के पैनल द्वारा पर्याप्त संसाधन क्वालिटी नियंत्रण वाले अनुमोदित विनिर्माण एकक के रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों का निर्यात करने के लिए, निर्यातकर्ता उपनियम (1) में उल्लिखित सूचना के साथ यह घोषणा भी प्रस्तुत करेगा कि निर्यात के लिए आशयित रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों का परेषण, अनुसूची–I में यथा अधिकथित क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करते हुए विनिर्मित किए गए हैं तो परेषण, इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

(3) उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना, विनिर्माता के परिसरों से परेषण के भेजे जाने से कम से कम सात दिन पूर्व दी जाएगी, जबकि उपनियम (2) के अधीन घोषणा सहित सूचना विनिर्माता के परिसरों से परेषण के भेजे जाने से कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाएगी ।

(4) निर्यातकर्ता अधिकरण को, निर्यात किए जाने वाले परेषण पर लगाए जाने वाले पहचान चिन्ह भी देगा ।

(5) उपनियम (1) के अधीन सूचना और उपनियम (2) के अधीन घोषणा, यदि कोई हो, के प्राप्त होने पर अधिकरण—

(क) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान अपना यह समाधान हो जाने पर कि विनिर्माता ने इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए अनुसूची I में यथा अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया है तथा इस संबंध में परिषद/अधिकरण द्वारा जारी किए गए निदेशों, यदि कोई हों, का पालन किया है, रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों के परेषण के निर्यात के लिए तीन दिन के भीतर निरीक्षण-प्रमाण पत्र जारी कर देगा । जहां विनिर्माता निर्यातकर्ता नहीं है, वहां परेषण का यथा आवश्यक सत्यापन तथा निरीक्षण जो अधिकरण द्वारा किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि उपरोक्त शर्तों का पालन किया गया है । अधिकरण नियमित अंतरालों पर यूनिट में जाएगा और परेषणों में से कुछ परेषणों की, यह सत्यापित करने के लिए स्थल पर जांच करेगा कि यूनिट द्वारा अपनाई गयी संसाधन क्वालिटी नियंत्रण पर्याप्त है । यदि विनिर्माण यूनिट में यह पाया जाता है कि उनमें विनिर्माण के किसी भी प्रक्रम पर अपेक्षित क्वालिटी नियंत्रण को नहीं अपनाया गया या अधिकरण के अधिकारियों की सिफारिशों का पालन नहीं किया गया है तो यह घोषित किया जाएगा कि यूनिट में संसाधन क्वालिटी नियंत्रण नहीं हैं । ऐसे मामलों में, यूनिट अपनी कमी को दूर करेगा और संसाधन क्वालिटी नियंत्रण का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नया आवेदन देगा ।

(ख) ऐसी दशाओं में जिनमें निर्यातकर्ता ने उपनियम 3 (ख) के अधीन निर्यात करने की मांग की है अपना यह समाधान हो जाने पर कि रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों का परेषण, किए गए निरीक्षण/परीक्षण के आधार पर मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, निरीक्षण के सात दिन के भीतर रंगलेप तथा संबद्ध उत्पादों के परेषण के निर्यात के लिए निरीक्षण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

परन्तु जहां अधिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है वहां वह निर्यात के लिए ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार कर देगा और ऐसे इंकार की सूचना उसके कारणों सहित निर्यातकर्ता को देगा ।

(6) ऐसी दशा में जहां विनिर्माता उपनियम 5(क) के अधीन निर्यात के लिए निर्यातकर्ता नहीं है या परेषण का उपनियम 5(ख) के अधीन निरीक्षण किया जाता है, वहां अधिकरण निरीक्षण की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पैकेजों को परेषण इस ढंग से सील करेगा कि सीलबंद पैकेजों में रद्दोबदल न की जा सके । परेषण की अस्वीकृति की दशा में यदि निर्यातकर्ता ऐसा चाहता है तो परेषण अधिकरण द्वारा सील बंद नहीं किया जाएगा किन्तु ऐसे मामलों में, निर्यातकर्ता इन नियमों में नियम 3 के अधीन कोई भी अपील करने का हकदार नहीं होगा ।

5. निरीक्षण का स्थान :—इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण—

(क) ऐसे उत्पादों के विनिर्माता के परिसरों पर;

या

(ख) ऐसे परिसरों पर किया जाएगा जहां निर्यातकर्ता ने माल प्रस्तुत किया है, परन्तु यह तब जब कि वहां निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

6. निरीक्षण फीस :—इन नियमों के अधीन निरीक्षण फीस के रूप में निर्यातकर्ता अभिकरण को प्रत्येक परेषण के पोत-पर्यन्त नि: शुल्क मूल्य के प्रत्येक एक सौ रुपए पर एक रुपया की दर से फीस देगा ।

7. अपील :—(1) नियम (4) के उपनियम (5) के अधीन प्रमाण-पत्र देने से अधिकरण द्वारा इंकार किए जाने से व्यक्ति कोई व्यक्ति, ऐसे इंकार की उसके द्वारा सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे विशेष पेनल को अपील कर सकेगा जिसमें कम से कम तीन तथा से अधिक अधिक सात व्यक्ति होंगे।

(2) विशेषज्ञों के पेनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य गैर-सरकारी होंगे ।

(3) विशेषज्ञों के पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।

(4) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

अनुसूची–I

[नियम 3 (क) देखें]

रंगलेप तथा संबंद्ध उत्पादों का प्रत्येक विनिर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि उसने अनुसूची–II में दिए गए नियंत्रण स्तरों के साथ नीचे अधिकथित उत्पाद के विनिर्माण, परिरक्षण तथा पैकिंग के विभिन्न प्रक्रमों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग किया है ।

1. कच्ची सामग्री नियंत्रण :

(क) प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री के गुणधर्मों को समादिष्ट करते हुए विनिर्माता द्वारा क्रय–विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे ।

(ख) कच्ची सामग्री के स्वीकृत परेषणों के साथ या तो प्रदायकर्ता का परीक्षण और निरीक्षण प्रमाण-पत्र होगा या क्रय–विनिर्देशों की अपेक्षाओं को समाविष्ट करते हुए निरीक्षण प्रमाण-पत्र होगा । जिस मामले में किसी विशिष्ट प्रदायकर्ता के लिए क्रेता द्वारा कम से कम 10 परेषणों में से एक की प्रति-जांच की जाएगी या क्रय की गई सामग्री का क्रेता द्वारा अपनी प्रयोगशाला में या प्रयोगशाला/परख सदन के बाहर अधिकथित क्रय विनिर्देशों से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण और परीक्षण किया जाएगा।

(ग) किए जाने वाले निरीक्षण या परीक्षण के लिए नमूना लेना अभिलिखित अन्वेषणों के आधार पर विनिर्माता द्वारा अधिकथित किया जाएगा ।

(घ) निरीक्षण या परीक्षण किए जाने के पश्चात्, स्वीकृत तथा अस्वीकृत सामग्री के पृथक्करण के लिए व्यवस्थित पद्धतियां यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाएंगी कि अस्वीकृत सामग्री का रंगलेप और संबद्ध उत्पादों के विनिर्माण में रंगलेप और संबद्ध उत्पादों के विनिर्माण में प्रयोग तो नहीं हो रहा है ।

(ङ) पूर्वोक्त नियंत्रणों के संबंध में विनिर्माता द्वारा नियमित और व्यवस्थित रूप में रखे गए अभिलेख वस्तुत: प्रयुक्त नियंत्रणों का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त होंगे ।

2. प्रक्रिया नियंत्रण :

(क) विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं जिनके अंतर्गत कच्ची सामग्री और मध्यवर्ती उत्पाद, यदि कोई हों, से संबंधित प्रक्रिया भी सम्मिलित है के लिए व्यौरेवार प्रक्रिया विनिर्देश विनिर्माता द्वारा कच्ची सामग्री और मध्यवर्ती उत्पादों के गुणधर्मों सहित अधिकथित किए जाएंगे ।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देश में यथा अधिकथित संसाधन के नियंत्रण के लिए उपकरण तथा उपस्करों की पर्याप्त सुविधाएं होंगी ।

(ग) यह सत्यापित करने के लिए कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान वस्तुत: प्रयुक्त नियंत्रण पर्याप्त था, विनिर्माता द्वारा अभिलेख रखे जाएंगे ।

3. उत्पाद नियंत्रण :

(क) अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद की जांच करने के लिए विनिर्माता के पास या तो अपनी परीक्षण सुविधाएं होंगी या उसकी पहुंच वहां तक होगी जहां ऐसी परीक्षण सुविधाएं विद्यमान हों ।

(ख) प्रत्येक बैच से प्रतिनिधि नमूना लिया जाएगा या। प्रपुंज नमूने को दो बराबर परीक्षण नमूनों में बांट दिया जाएगा । ऐसा एक परीक्षण नमूना विनिर्माता द्वारा उत्पादों की अपेक्षाओं के लिए परीक्षित किया जाएगा तथा दूसरा नमूना उसकी विशिष्टताओं सहित कम-से-कम छ: मास के लिए निर्देश नमूने के रूप में रखा जाएगा ।

(ग) नमूना लेने और परीक्षण के बारे में अभिलेख इस संबंध में वस्तुत: प्रयुक्त नियंत्रणों की पर्याप्तता का सत्यापन करने के लिए नियमित और व्यवस्थित रूप में रखे जाएंगे ।

(घ) उत्पाद की जांच करने के लिए नियंत्रण के न्यूनतम स्तर अनुसूची–II में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. परिरक्षण नियंत्रण :

विनिर्माता द्वारा मध्यवर्ती तथा अन्तिम उत्पादों के परीक्षण के लिए अपेक्षाएं अधिकथित की जाएंगी।

5. पैकिंग नियंत्रण :

(क) अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के न्यूनतम का समाधान किए जाने की दृष्टि से पैकिंग विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे तथा उन्हें कठोरता से कार्यान्वित किया जाएगा।

(ख) पैकिंग के संबंध में प्रयुक्त नियंत्रणों के लिए अभिलेख विनिर्माता द्वारा व्यवस्थित तथा नियमित रूप से रखे जाएंगे।

अनुसूची–2

नियंत्रण के स्तर

(क) सारणी–1 में उल्लिखित उत्पादों के लिए

क्रम सं.	अपेक्षाएं	संदर्भ	नमूनों की संख्या	आवृत्ति
1	2	3	4	5
1.	गाढ़ापन	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
2.	शुष्कन समय	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
3.	फिनिश	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
4.	प्रति 10 लिटर भार	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
5.	रंग	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
6.	खरोंच कठोरता	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
7.	लचीलापन तथा आसंजन	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
8.	अपखंडन परीक्षण	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
9.	रंगों का पक्कापन	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
10.	अम्ल मूल्य	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
11.	प्रज्वलन ताप	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
12.	क्षारीयता परीक्षण	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
13.	वाष्पशील पदार्थ	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
14.	पानी का प्रतिरोध	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
15.	अम्ल का प्रतिरोध	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
16.	क्षारीय प्रतिरोध	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
17.	पिसाई की सूक्ष्मता	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
18.	स्थायिता	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
19.	चमक धारणशीलता	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
20.	पानी की मात्रा (—)	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
21.	आर्द्र अपारदर्शिता	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
22.	परावैद्युत क्षमता परीक्षण	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
23.	कॉपर इनेमल विद्युत रोधन का प्रतिरोध	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच
24.	ताम्र पर वार्निश की प्रतिक्रिया	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच

(ख) सारणी-II में उल्लिखित उत्पादों के लिए :

(i) सभी प्रकार के, तैयार मिश्रित रंगलेपे और इनेमल, सभी प्रकार की संश्लिष्ट वार्निशों को छोड़कर (फिनिशिंग के लिए संश्लिष्ट वार्निशों को छोड़कर) और सह उष्मासह वार्निशों (वायु शुष्कित, बिटुमन प्रकार) प्लास्टिक और एक्रलिक नाइट्रोसेल्यूलोज प्रलाक्षा स्वच्छ या रंग मिश्रित को छोड़कर सभी प्रकार के इमल्शन रंगलेप, जिसमें फिलर या प्राइमर या सरफसर, पेस्ट रंगलेपे और पेस्ट डिस्टम्पर भी सम्मिलित हैं।

क्रम सं.	अपेक्षाएं	संदर्भ	नमूनों की संख्या	आवृति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	गाढ़ापन	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
2.	शुष्कन समय	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
3.	फिनिश	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
4.	प्रतिलिटर/गैलन भार	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
5.	रंग	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
6.	खरोंच कठोरता	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
7.	लचीलापन तथा आसंजन	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
8.	अम्ल मुक्त/अम्लीयता	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
9.	क्षारता	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
10.	विद्युत प्रबलता	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
11.	प्रवण की दशा में संक्षारण से संरक्षण	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
12.	वाष्पशील पदार्थ	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
13.	विषाक्तता परख	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
14.	काल प्रभावन	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
15.	तेल का प्रभाव	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
16.	प्रज्वलन ताप	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
17.	आच्छादन क्षमता	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
18.	अन्य परीक्षण	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो

(ii) शुष्क डिस्टैम्पर, चूर्ण रंग तथा सीमेंट रंग

1	2	3	4	5	6
1.	शुष्कन का समय (कठोरता तथा पुनः कोटिंग की विशेषताएं)	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त एक मानक विनिर्देश		प्रति बैच	जब भी लागू हो
2.	फिनिश	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त एक मानक विनिर्देश		प्रति बैच	जब भी लागू हो
3.	रंग	इस प्रयोजन के लिए मान्यत प्राप्त एक मानक विनिर्देश		प्रति बैच	जब भी लागू हो
4.	प्रकाश में रंग पक्कता	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त एक मानक विनिर्देश		प्रति बैच	जब भी लागू हो
5.	छलनी में अवशेष	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त एक मानक विनिर्देश		प्रति बैच	जब भी लागू हो
6.	शुष्क रगड़ने पर प्रतिरोध	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त एक मानक विनिर्देश		प्रति बैच	जब भी लागू हो
7.	जल विकर्षण क्षमता	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त एक मानक विनिर्देश		प्रति बैच	जब भी लागू हो
8.	मिश्रित रंगलेप की घट जीवन	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त एक मानक विनिर्देश		प्रति बैच	जब भी लागू हो
9.	अनुरक्षण गुणधर्म	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक एक विनिर्देश		प्रति बैच	जब भी लागू हो
10.	फैलाव क्षमता	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक एक विनिर्देश		प्रति बैच	जब भी लागू हो
11.	फैलाव का समय	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक एक विनिर्देश		प्रति बैच	जब भी लागू हो
12.	क्षमता	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक एक विनिर्देश		प्रति बैच	जब भी लागू हो
13.	अन्य परीक्षण	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक एक विनिर्देश		प्रति बैच	जब भी लागू हो

टिप्पण :—सीमेंट रंगलेप, कार्बनिक योजकों से मुक्त होना चाहिए।

(iii) रंगलेप के लिए विरलक :—

1	2	3	4	5	6
1.	रंग	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त एक मानक विनिर्देश		प्रति बैच	जब भी लागू हो
2.	आपेक्षित घनत्व	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त एक मानक विनिर्देश		प्रति बैच	जब भी लागू हो
3.	आसवन रेंज	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त एक मानक विनिर्देश		प्रति बैच	जब भी लागू हो
4.	वाष्पीकरण पर का अवशेष	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त एक मानक विनिर्देश		प्रति बैच	जब भी लागू हो
5.	काउरी बूटानोल मान	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक एक विनिर्देश		प्रति बैच	जब भी लागू हो

1	2	3	4	5	6
6.	हाईड्रोकार्बन विलायकों के लिए एनिलिन बिन्दु और मिश्रित एनिलिन बिन्दु	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
7.	संक्षारक गंधक के लिए परीक्षण	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
8.	क्लोरीनित हाईड्रोकार्बन विलायक पदार्थों तथा बेंजीन से मुक्ति के लिए परीक्षण	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
9	अम्ल धुलाई परीक्षण	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
10.	हाइड्रोजन सल्फाईड तथा मिरकैपटैन के लिए परीक्षण	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
11.	सीसे से मुक्ति	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
12.	प्रज्वलन ताप	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
13.	विक्रेता तथा क्रेता के बीच तय पाया गया विशिष्टि परीक्षण, यदि कोई हो	इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो

(4) रंगलेप के लिये संश्लिष्ट रेजिन :—

1	2	3	4	5	6
1.	स्थानता	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
2.	अम्ल मान	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
3.	एम. प्वाइंट (गलन बिंदु)	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
4.	स्वच्छता	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
5.	अन्य परीक्षण	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो

(5) रंगलेप के लिए प्रसंस्कृत तेल या रेंगलेप के लिए शुष्कन या अर्धशुष्कन तेलों:—

1	2	3	4	5	6
1.	रंग	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
2.	विशिष्ट गुरुत्व (या घनत्व)	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
3.	अम्ल मान	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
4.	स्वतुल्य तालिका	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
5.	गलन (या पिडन) सें. ग्रे. बिंदु	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
6.	आयोडिन मान	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
7.	साबुनीकरण मान	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
8.	अन्य परीक्षण	इस प्रयोजन के लिय मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो

(6) बिटुमैनस कोटिंग :—

1	2	3	4	5	6
1.	विशिष्ट गुरुत्व	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
2.	कोमलता बिंदु	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
3.	वेधन परीक्षण	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
4.	छीलन परीक्षण	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
5.	आघात प्रबलता	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
6.	आनमन परीक्षण	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
7.	भस्म अंश	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
8.	अन्य परीक्षण	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो

(7) एल्युमिनियम पेस्ट :—

1	2	3	4	5	6
1.	एल्युमियनम चूर्ण	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
2.	वर्कमान	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
3.	छानने पर अवशेष (150 माइक्रोन, 75 माइक्रोन, 53 माइक्रोन भा०मा. छननी)	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
4.	चिकनाई अंश	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
5.	फिनिश	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
6.	स्थिरण विशिष्टताएं	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
7.	वाष्पशील पदार्थ	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
8.	कोटिंग गुणधर्म	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
9.	कुल अवशेष जिसके अन्तर्गत तांबा और सीसा है	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो
10.	अन्य परीक्षण	इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश	एक	प्रति बैच	जब भी लागू हो

अनुसूची—3

[नियम 3 (ख) देखिए]

1.1 रंगरोगन और संबद्ध उत्पादों का परेषण, अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों से उसकी अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण और परीक्षण के अधीन होगा ।

1.2 जब तक कि संविदात्मक विनिर्देशों में अन्यथा उल्लिखित न हो, नमूना मापदंड और लिए जाने वाले नमूनों की संख्या अधिनियम की धारा 6 के अधीन अधिसूचित न्यूनतम अपेक्षाओं के अनुसार होगी ।

1.3 एक लोट से लिए गए प्रत्येक नमूने का भार प्रति 10 लिटर के लिए, जहां भी लागू हो, अलग-अलग परीक्षण किया जाएगा । यदि वे विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप पाए जाते हैं तो उसी लाट से लिए गए अलग-अलग नमूनों को एक सम्मिलित नमूना बनाने के लिए एक साथ संमिश्रित किया जाएगा । तब उसे दो एक समान परीक्षण नमूनों में विभाजित किया जाएगा । ऐसे एक परीक्षण नमूने का संगत विशिष्टिताओं के लिए परीक्षण किया जाएगा और दूसरे को कम से कम छः मास के लिए उसकी विशिष्टियों सहित निर्देश नमूने के रूप में रखा जाएगा ।

1.4 यदि निर्यात संविदा में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है तो परीक्षण की पद्धति सुसंगत भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार होगी ।

[फा. सं. 6(5)/85-ई. आई. एंड ई. पी.]

एन. एस. हरिहरन, निदेशक

S.O. 309.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Export of Paints and Allied Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1987.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (Central Act 22 of 1963);

(b) "Agency" means any one of the agencies established under section 7 of the Act at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras ;

(c) "paints and allied products" means

TABLE-I

(i) Synthetic enamels

(ii) Insulating varnishes (Air drying, Bitumen type)

(iii) Synthetic varnishes, finishing (General purposes)

(iv) Emulsion paints (Plastic/Acrylic emulsion)

TABLE-II

(i) Ready-mixed paints and enamals of all types including primers, fillers, under-coating and finishing except synthetic enamels.

(ii) Varnishes of all type (prepared from natural resin or synthetic resins or both) except synthetic varnishes finishing (general purposes) and insulating varnishes (air drying, bitumen type).

(iii) Emulsion paints of all types except elastic and acrylic

(iv) Nitrocellulose lacquers, clear or pigmented including fillers, primers or surfaces.

(v) Paste paints and paste distempers

(vi) Dry distempers, lime colours and cement colours.

(vii) Cement paints

(viii) Thinners for paints

(ix) Synthetic resin for paints

(x) Processed oils for paints and drying or semidrying oils for paints.

(xi) Bituminous coatings

(xii) Aluminium paste

(d) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(e) "Schedules" means Schedules appended to these rules.

3. Basis of Inspection.—Inspection of paints and allied products for export shall be carried out with a view to seeing that the paints and allied products conform to the standard specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (Central Act 22 of 1963)-

(a) by ensuring that the products have been manufactured by exercising necessary in-process quality control as specified in Schedule-I;

OR

(b) on the basis of inspection and testing carried out in the manner specified in Schedule-III.

4. Procedure of Inspection.—(1) An exporter intending to export a consignment of paints and allied products shall give an intimation in writing to the agency furnishing therein details of the contractual specifications alongwith a copy of the export contract or order to enable the Agency to carry out inspection in accordance with rule 3.

(2) For export of paints and allied products of a manufacturing unit approved as having adequate in process quality control by the panel of experts constituted by the Agency for this purposes. The exporter shall also submit alongwith the intimation mentioned in sub-rule (1) a declaration that the consignment of paints and allied products intended for export has been manufactured by exercising quality control as laid down in Schedule-I and that the consignment conforms to the standard specifications recognised for the purpose.

(3) Every intimation under sub-rule (1) above shall be given not less than seven days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises while the intimation alongwith the declaration under sub-rule (2) shall be given not less than three days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises.

(4) The exporter shall furnish to the Agency the identification marks applied on the consignment to be exported

(5) On receipt of the intimation under sub-rule (1) and the declaration, if any, under sub-rule (2), the agency

(a) On satisfying itself that during the process of manufacture, the manufacturer has exercised adequate quality control as laid down in Schedule-I to manufacture the product to conform to the standard specifications recognised for the purpose and the manufacturer had followed the instructions, if any, issued by the Council/Agency in this regard, shall within three days issue an inspection certificate for export of the consignment of paints and allied products. In case where the manufacturer is not the exporter, such verification and inspection of consignment as necessary shall be carried out by the agency as to ensure that the above conditions have been complied with. The agency shall visit units at regular intervals and conduct spot check on some of the consignments to verify the adequacy of in-process quality control adopted by the unit. If the manufacturing unit is found not adopting the required quality control measures or recommendations of the officers of the Agency at any stage of manufacture the unit shall be declared as not having adequate in-process quality control. In such cases, the unit shall rectify deficiencies and apply afresh for the approval of in-process quality control.

(b) In case where the exporter has sought export under sub-rule 3(b), on satisfying itself that the consignment of paints and allied products conform to the standard specifications, on the basis of inspection/testing carried out shall within seven days of inspection issue an inspection certificate for export of the consignment of paints and allied products;

Provided that where the agency is not so satisfied it shall refuse to issue a certificate of inspection for export and shall communicate such refusal to the exporter within the said seven days alongwith the reasons therefor.

(6) In case where the manufacturer is not the exporter for export under sub-rule 5(a) or the consignment is inspected under sub-rule 5(b), the Agency shall immediately after completion of the inspection seal the packages in the consignment in a manner so as to ensure that the sealed packages cannot be tampered with. In case of rejection of the consignment if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the Agency, but in such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal under rule 8 of these rules.

5. Place of Inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out either—

(a) at the premises of the manufacturer of such products;

or

(b) at the premises at which the goods are offered by the exporter provided adequate facilities for inspection and testing exist therein.

6. Inspection Fee.—A fee at the rate of one rupee for every one hundred rupees of FOB value of each consignment shall be paid by the exporter to the agency as inspection fee under these rules.

7. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4 may, within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government;

(2) A minimum of two thirds of the total membership of the panel of experts shall be non-officials;

(3) The quorum for the panel of experts shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days of its receipt.

SCHEDULE-I

[See under rule 3(a)]

Every manufacturer of paints and allied products shall be ensured by effecting the following controls at different stages of manufacture, preservation and packing of the product as

laid down below together with the levels of control as set out in the Schedule-II.

(i) Raw material Control :

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of raw materials to be used.

(b) The accepted consignments of raw materials shall either be accompanied by a supplier's test and inspection certificate corroborating the requirements of the purchase specifications in which case counter checks shall be conducted atleast once in 10 consignments by the purchaser for a particular supplier or the purchased materials shall be regularly tested and inspected by the purchaser in own laboratory or in an outside laboratory/test house to ensure conformity with the laid down purchase specifications.

(c) The sampling for inspection or test to be carried out shall be laid down by the manufacturer based on the recorded investigations.

(d) After the inspection or test is carried out, systematic methods shall be adopted in segregating the accepted and rejected materials to ensure that the rejected materials are not used in the manufacture of paints and allied products.

(e) Records in respect of the aforesaid controls regularly and systematically maintained by the manufacturer shall be adequate to verify the control actually exercised.

(ii) Process Control :

(a) Detailed process specification for different processes of manufacture including those for raw materials and intermediate products, if any, shall be laid down by the manufacturer alongwith the properties of raw materials and intermediate products.

(b) Equipment and instrumentation facilities shall be adequate to control the process as laid down in the process specification.

(c) Records shall be maintained by the manufacturer to verify that the controls actually exercised during the process of manufacturer are adequate.

(iii) Product Control :

(a) The manufacturer shall have either his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to check up whether the product conforms to the standard specification recognised under Section 6 of the Act.

(b) A representative sample shall be drawn from each batch. The bulk sample shall be divided into two equal test samples. One such test sample shall be tested by the manufacturer for the requirements of the products and the other preserved as referee samples alongwith its particulars for atleast six months.

(c) Records in respect of sampling and tests shall be regularly and systematically maintained to verify the adequacy of the controls in this regard actually exercised.

(d) The minimum levels of control to check the product shall be as specified in Schedule-II.

(iv) Preservation Control.—The requirements for preservation of intermediary final products shall be laid down by the manufacturer.

(v) Packing Control :

(a) A packing specification shall be laid down with a view to satisfying minimum of the standard specifications recognised under section 6 of the Act and shall be rigidly implemented.

(b) Records in respect of the controls exercised in respect of packing shall be maintained by the manufacturer regularly and systematically.

SCHEDULE—II

LEVELS OF CONTROL

(a) For products mentioned in Table-I

S. No.	Requirement	Reference	No. of samples	Frequency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Consistency	Standard specifications recognised for the pusrpose	One	Per batch
2.	Drying time	"	"	"
3.	Finish	"	"	"
4.	Weight per 10 litres	"	"	"
5.	Colour	"	"	"
6.	Scorich hardness	"	"	"
7.	Flexibility & adhesion	"	"	"
8.	Stripping test	"	"	"
9.	Colour fastness	"	"	"
10.	Acid value	"	"	"
11.	Flash Point	"	"	"
12.	Alkalinity test	"	"	"
13.	Volatile matter	"	"	"
14.	Resistance to water	"	"	"
15.	Resistance to acid	"	"	"
16.	Resistance to alkali	"	"	"

1	2	3	4	5
17.	Fineness of grind	,,	,,	,,
18.	Viscosity	,,	,,	,,
19.	Gloss retention	,,	,,	,,
20.	Water content(%)	,,	,,	,,
21.	Wet opacity	,,	,,	,,
22.	Di-electric strength test	,,	,,	,,
23.	Resistance to coil enamel insulation	,,	,,	,,
24.	Reaction of varnish with copper	,,	,,	,,

(b) For products mentioned in Table-II

(i) Ready mixed paints and enamels of all types except synthetic varnishes of all types (except synthetic varnishes for finishing) and insulating varnishes (air drying, bitumen type), emulsion paints of all types except plastic and acrylic nitrocellulose lacquers, clear or pigmented including fillers, primers or surfacers, paste paint and paste distempers.

S. No.	Requirement	Reference	No. of sample	Frequency	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Consistency	Standard specifications recognised for the purpose	One	per batch	Whenev e ap plicabl
2.	Drying time	,,	,,	,,	,,
3.	Finish	,,	,,	,,	,,
4.	Weight per litre/gallon	,,	,,	,,	,,
5.	Colour	,,	,,	,,	,,
6.	Scratch hardness	,,	,,	,,	,,
7.	Flexibility and adhesion	,,	,,	,,	,,
8.	Acid value/acidity	,,	,,	,,	,,
9.	Alkalinity	,,	,,	,,	,,
10.	Electric strength	,,	,,	,,	,,
11.	Protection against corrosion under conditions of condensation	,,	,,	,,	,,
12.	Volatile matter	,,	,,	,,	,,
13.	Toxicant availability test	,,	,,	,,	,,
14.	Ageing	,,	,,	,,	,,
15.	Effect of oil	,,	,,	,,	,,
16.	Flash point	,,	,,	,,	,,
17.	Covering capacity	,,	,,	,,	,,
18.	Other tests	,,	,,	,,	,,

(ii) Dry distempers, lime colours and cement colours

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Drying time (hardening and recoating properties)	Standard specifications recognised for the purpose	One	Per batch	Whenever ap plicable
2.	Finish	,,	,,	,,	,,
3.	Colour	,,	,,	,,	,,
4.	Fastness to light	,,	,,	,,	,,
5.	Residue on sieve	,,	,,	,,	,,
6.	Resistance to dry rubbing	,,	,,	,,	,,
7.	Water repellancy	,,	,,	,,	,,
8.	Pot life of mixed paint	,,	,,	,,	,,
9.	Keeping properties	,,	,,	,,	,,
10.	Spreading capacity	,,	,,	,,	,,
11.	Spreading time	,,	,,	,,	,,
12.	Capacity	,,	,,	,,	,,
13.	Other tests	,,	,,	,,	,,

Note : Cement paint shall be free from organic binders.

(iii) Thinners for paints

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Colour	Standard specifications recognised for the purpose	One	Per batch	Whenever applicable
2.	Relative density	"	"	"	"
3.	Distillation Range	"	"	"	"
4.	Residue on evaporation	"	"	"	"
5.	K auri Butanol value	"	"	"	"
6.	Aniline point and mixed aniline point for hydrocarbon-solvent	"	"	"	"
7.	Test for corrosive sulphur	"	"	"	"
8.	Test for freedom from chlorinated hydrocarbon solvents and benzene	"	"	"	"
9.	Acid wash test	"	"	"	"
10.	Test for hydrogen sulphide and mercapatans	"	"	"	"
11.	Freedom from lead	"	"	"	"
12.	Flash point	"	"	"	"
13.	Specific test, if any, as agreed between buyer and seller	"	"	"	"

(iv) Synthetic resin for paints

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Viscosity	Standard specifications recognised for the purpose	One	per batch	Whenever applicable
2.	Acid value	"	"	"	"
3.	M. Pt.	"	"	"	"
4.	Clarity	"	"	"	"
5.	Other tests.	"	"	"	"

(v) Processed oils for paints and drying or semi-drying oils for paints

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Colour	Standard specifications recognised for the purpose	One	per bath	Whenever applicable
2.	Sp. Gr. (or density)	"	"	"	"
3.	Acid value	"	"	"	"
4.	Refractive Index.	"	"	"	"
5.	Melting (or solidification) Point °C	"	"	"	"
6.	Iodine value	"	"	"	"
7.	Saponsification value	"	"	"	"
8.	Other tests.	"	"	"	"

(vi) Bituminous caotings

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Specific gravity	Standard specifications recognised for the purpose	One	Per batch	Whenever applicable
2.	Softening point	"	"	"	"
3.	Penetration test	"	"	"	"
4.	Peel test	"	"	"	"
5.	Impact strength	"	"	"	"
6.	Sag test	"	"	"	"
7.	Ash content	"	"	"	"
8.	Other tests	"	"	"	"

(vii) Aluminium paste

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aluminium powder	Standard specifications recognised for the purpose	One	per batch	whenever applicable
2.	Leafing value	"	"	"	"
3.	Residue on sieve (150 micron, 75 micon, 53 micron I.S. Sieves)	"	"	"	"
4.	Grease content	"	"	"	"
5.	Finish	"	"	"	"
6.	Settling properties	"	"	"	"
7.	Volatile matter	"	"	"	"
8.	Keeping properties	"	"	"	"
9.	Total impurities including copper and lead	"	"	"	"
10.	Other tests	"	"	"	"

SCHEDULE-III

[See under rule 3(b)]

1.1 The consignment of paints and allied products shall be subject to inspection and testing to ensure conformity of the same to the standard specifications recognised under section 6 of the Act.

1.2 Unless otherwise mentioned in the contractual specifications, the sampling criteria and the number of samples to be drawn shall be as per the minimum requirements notified under section 6 of the Act.

1.3 Each sample drawn from a lot shall be individually tested for weight per 10 litre where applicable. If they are found to be conforming to the specified standard individual samples drawn from the same lot shall be blended together to make composite sample and then shall be divided into two equal test samples. One such test sample shall be tested for the relevant characteristics and the other preserved as referee sample along with its particulars for atleast six months.

1.4 If not otherwise specified in the export contract, methods of testing shall be as per relevant Indian Standards Specifications.

[F. No. 6(5)/85-EI&EP]
N. S. HARIHARAN, Director

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1987

का. आ. 310 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में बी. एल.एच. जे. से बलोल जी. जी. एस० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

बी. एल. एच. जे. से बलोल जी. जी. एस. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना ता लुक : मेहसाना

गाँव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टीयर
मीठा	430	0	07	32
	429/1	0	08	64
	429/2			
	429/3	0	07	26
	429/4			
	428	0	17	16
	426	0	03	48
	425/1	0	19	68
	400/2	0	03	36
	400/1	0	07	32
	400/3	0	11	16
	399	0	01	32

[सं. ओ-12016/4/87-ओ एन जी-डी-4]

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 20th January, 1987

S.O. 310.—Whereas it appear to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from BLHJ to BALOL G.G.S. in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroluem and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from BLHJ to BALOL G.G.S.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
1	2	3		4
Mitha	430	0	07	32
	429/1	0	08	64
	429/2			
	429/3	0	07	26
	429/4			
	428	0	17	16
	426	0	03	48
	425/1	0	19	68
	400/2	0	03	36
	400/1	0	07	32
	400/3	0	11	16
	399	0	01	32

[No. O 12016/4/87-O.N.G.D-4]

का. आ. 311:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस. एन. बी. एफ. से (वाया एस. एन. के.) एस. एस. सी. टी. एफ. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एस. एन. बी. एफ. से (वाया एस. एन. के.) एस. एस. सी. टी. एफ. तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : मेहसाना

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	आरे.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
कसलपुरा	940	0	03	60
	कार्ट ट्रैक	0	01	20
	827	0	10	44
	826	0	08	88
	831	0	01	44
	832	0	03	00

[स. ओ-12016/3/87-ओ. एन. जी. डी-4]

S.O. 311.—Whereas it appear to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum SNBF to (Via SNK) S.S. CTF i.e. N.E.S.S.C.T.F. in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed thereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara, (390 009).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNBF to (Via SNK) S.S. CTF i.e. N.E. S.S.CTF.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Kasalpura	940	0	03	60
	Cart Track	0	01	20
	827	0	10	44
	826	0	08	88
	831	0	01	44
	832	0	03	00

[No. O-12016/3/87-O.N.G. D-4]

का. आ. 312 :—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 2766 तारीख 23-7-86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एस.बी.डी.जे. से शोभासन सी.टी.एफ. तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात, जिला—मेहसाना, ता.—मेहसाना

गांव	ब्लाक नं.	हे.	आरे	सें.
हेबुआ	102	0	03	24
	104	0	06	36

[सं. O-12016/110/86-ओ एन जी-डी-4]

पी० के० राजगोपालन, डैस्क अधिकारी

S.O. 312.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 2766 dated 23-7-866 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And fufrther in exercise of power conferred by sub-section (4) of the section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the pulication of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from SBDJ to SOB. CTF

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	
Hebuva	102	0	03	24
	104	0	06	36

[No. O-12016/110/86/O.N.G.-D-4]

P.K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 21 जनवरी 1987

का०आ० 313 :—भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 (1890 का अधिनियम 9) की धारा 82बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार श्री भिखारी राम, अपर जिला एवं सेशन्स न्यायाधीश, पालामउ को 6-8-1986 को गढ़वा रोड और तोलरा स्टेशन के बीच 162-डाउन, अमृतसर-टाटा एक्सप्रेस की हुए दुर्घटना से उत्पन्न सभी दावों को निपटाने के लिए तदर्थ दावा आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है। उनका मुख्यालय डाल्टनगंज में होगा।

[सं. 86/ई (ओ) II/1/3]

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 21st January, 1987

S.O. 313.—In exercise of the powers conferred by section 82B of the Indian Railways Act, 1890 (Act IX of 1890), the Central Government hereby appoints Shri Bhikari Ram, Addl. District and Sessions Judge, Palamau as Ad hoc Claims Commissioner to deal with all the claims arising out of accident of 162 DN, Amritsar-Tata Express on 6-8-1986 between Garwa Road and Tolra Station. His Headquarters will be at Daltonganj.

[No 86/E(O)/II/1/3]

का०आ० 314:—भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 (1890 का अधिनियम 9) की धारा 82 बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री गोपीनाथ चन्द्रा अपर जिला न्यायाधीश, धनबाद को 21-7-86 को गोमो में हुई 28 अप मौर्य एक्सप्रेस की दुर्घटना से उत्पन्न सभी दावों को निपटाने के लिए तदर्थ आधार पर दावा आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है । उनका मुख्यालय धनबाद में होगा ।

[सं. 86/ई (ओ) II/1(3)]

एम. एम. वैश, सचिव (रेलवे बोर्ड)

S.O. 314.—In exercise of the powers conferred by section 82B of the Indian Railways Act, 1890 (Act IX of 1890), the Central Government hereby appoints Shri Gopinath Chandra, Addl. District Judge, Dhanbad as Adhoc Claims Commissioner to deal with all the claims arising out of accident of 28 UP Maurya Express at Gomah on 21-7-1986. His Headquarters will be at Dhanbad.

[No. 86/E(O)II/1/3]

S. M. VAISH, Secy.,
Railway Board.

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1987

का. आ. 315:—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने अनपर्ति टेलीफोन केन्द्र, करणाटका सर्किल, में दिनांक 7-2-1987 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-8/87-पी एच बी]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 22nd January, 1987

S.O. 315.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specified 7-2-1987 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Anaparthy Telephone Exchange, Andhra Pradesh Telecom. Circle.

[No. 5-8-/87-PHB]

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1987

का.आ. 316:—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किये गये भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने सिंधानूर टैलीफोन केन्द्र, कर्नाटक सर्किल, में दिनांक 7-2-1987 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-7/87-पी एच बी]

के.पी. शर्मा, सहायक महानिदेशक (पी.एच.बी.)

New Delhi, the 27th January, 1987

S.O. 316.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Department of Telecommunications, hereby specified 7-2-1987 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Sindhanoor Telephone Exchange, Karnataka Telecom. Circle.

[No 5-7/87-PHB]

K. P. SHARMA, Asstt. Director General (PHB)

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1987

का.आ. 317:—मैसर्स सी.जे. पटेल तम्बाकू प्रोडक्टस प्रा.लि., एम.जी. रोड, सागर (मध्य प्रदेश) (एम.पी./2814) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) (की धारा 17 की उपधारा 2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल नहीं है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[एस-35014(280)/86-एस.एस-2]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 13th January, 1987

S.O. 317.—Whereas Messrs C. J. Patel Tobacco Products Private Limited, M.G. Road, Sagar (Madhya Pradesh) (M.P.| 2814) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provided Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Prividnt Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme correspondingly, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under his Scheme are reduced in any maner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assued to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|280|86-SS-II]

का.आ. 218 :—मैसर्स महेर सिमेन्ट, पोस्ट आफिस-सरखानगर—485772, महेर जिला—सतना (मध्य प्रदेश) (एम.पी./4767) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3क के खण्ड—क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो वह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[एस-35014(281)/86-एस.एस.-2]

S.O. 318.—Whereas Messrs Malhar Cement, P.O. Sarla Nagar-485772, Malhar, Distt. Satna (Madhya Pradesh) (MP/4767) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said estalishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Privident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under his Scheme are reduced in any maner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assued to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(281)/86-SS-II]

का० आ० 319.—मैसर्स एम० पी० स्टेट को-ओ० हाऊसिंग फैडरेशन लि०, सहकार भवन, नोरथ टी० टी० नगर, भोपाल (एम० पी०/3321) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की

सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा–2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3–क के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014/279/86-एस एस-II]

S.O. 319.—Whereas Messrs M.P. State Co-operative Housing Federation Limited, Sahjar Bhavan, North T.T. Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh (MP/3321) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payemnt of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under his Scheme are reduced in any matter, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assued to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

[No. S-35014(279)/86-SS-II]

का०आ० 320:—मैसर्स दि चुरू सेन्ट्रल को-ऑ० बैंक लि०, चुरू (राजस्थान) (आर० जे०/3368) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे; प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[एस-35014 (278)/86 - एस० एस-2]

S.O. 320.—Whereas Messrs The Churu Central Co-operative Bank Limited, Churu, Rajasthan (RJ/3668) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinfater referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under his Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assued to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/278/86-SS-II]

का० आ० 321:—मैसर्स—सागर को०ओ० मिल्क प्रोड्यूसर्ज यूनियन लि., सागर मध्य प्रदेश (एम.पी./3748) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा का प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता,

है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किसे गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014(283)/86-एस.एस.-2]

S.O. 321.—Whereas Messrs Sagar Co-opeartive Milk Producers Union Limited, Sagar, Madhya Pradesh (MP|3748) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident &. Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Privident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Under the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

[No. S-35014(283)|86-SS-II]

का. आ. 322.—मैसर्स चोपड़ा मैटल प्रा. लि. 8-बी, हैवी इन्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर-342003 (आर.जे./3614) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे

उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि की या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं०एस-35014(284)/86-एस एस-2]

S.O. 322.—Whereas Messrs Chopra Metal Private Limited, 8-B Heavy Industrial Area, Jodhpur-342003(RJ 3614) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act, and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto,

the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient feature thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

[No. S-35014(284)/86-SS-II]

का.आ. 322:—मैसर्स जबलपुर को. ओ. मिल्क प्रोड्यूसर्ज यूनियन लि., इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, अदारताल, जबलपुर, मध्य प्रदेश–482004 (एम. पी./3746) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध, अधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा–2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा 3–क के खंड–क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो, कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बताए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे ; प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी अतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014(285)/86-एस.एस-2]

S.O. 323.—Whereas Messrs Jabalpur Co-operative Milk Producers Union Limited, Industrial Estate, Andhartal, Jabalpur, M.P. (MP/3746) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable apportuinity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to any the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(285)/86-SS-II]

का. आ. 324.—मैसर्स मेहता वेजीटेबल प्रोडक्टस (प्रा०) लि., चित्तौड़गढ़ राजस्थान-312001 (आर.जे./1605) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खंड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती है जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के किसी कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम की नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[एस-35014(282)/86-एस.एस-2]

S.O. 324.—Whereas Messrs Mehta Vegetable Products (Private) Limited, Chittorgarh (Rajasthan) 312001 (RJ/1605) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident, Fund Commissioner Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(282)/86-SS-II]

का. आ. 325 मैसर्स—भोपाल को-ओ. सेन्ट्रल बैंक लि., 24-25 न्यू मार्केट, टी. टी. नगर, भोपाल (एम. पी./2316) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, (1952 का 17) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है (की धारा 17 की उपधारा 2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उक्त लेखा शीर्ष के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रशासन का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी का व्ययगतहो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[एस-35014(277)/86-एस. एस.-2]

S.O. 325.—Whereas Messrs Bhopal Co-operative Central Bank Limited, 24/25 New Market, T.T Nagar, Bhopal (MP)/2516) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him

as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employee under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(277)/86-SS-III]

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1987

शुद्धि पत्र

का. आ. 326.—तारीख 9 अगस्त, 1986 के भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के तारीख 24 जुलाई, 1986 के आदेश संख्या का. आ. 2797 के पृष्ठ 3180 की तीसरी पंक्ति में "क्षेत्रीय कार्यालय" शब्दों के पश्चात् "और स्थानीय कार्यालय" शब्द पढ़ें।

[संख्या ई-11012/1/86-एस. एस. 1]

New Delhi, the 14th January, 1987

CORRIGENDUM

S.O. 325.—In the order of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2797, dated the 24th July, 1986, published in the Gazette of India, Part II, Section 3 sub-section (ii) dated 9th August, 1986, at page 3181, in line 1, after the words "Regional Office" read "and Local Offices".

[E-11012/1/86-SS. I]

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1987

का. आ. 327.—मैसर्स इण्डियन डाइस्टाफ इण्डस्ट्रीज लि., शाहद रेलवे स्टेशन के निकट, पोस्ट बाक्स नं. 227, कल्याण—421304 (एम. एच./1402) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1902 तारीख 2-4-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 6-4-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 5-4-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय करेगा और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एफ-35014/78/83-पी. एफ.-2/एन. एस.-2]

New Delhi, the 16th January, 1987

S.O. 327.—Whereas Messrs Indian Dyestuff Industries Limited, Near Shahad Railway Station, Post Box No. 227, Kalyan-421304 (MH/1492) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in Continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 1902 dated the 2-4-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 6-4-1986 upto and inclusive of the 5-4-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would

be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/ nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one moth from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/78/83-PF-II-SS-II]

का.आ. 328.—मैसर्स रणबक्सी लैबोटरीज लि., ओखला, नई दिल्ली-110020 (डी. एल./1546) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3658 तारीख 19-7-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 24-9-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 24-9-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा ।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिदर्शिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त देहली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो

यहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्दाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमा कृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एफ-35014/90/83-पी.एफ.-2/एस.एस-2]

S.O. 328.—Whereas Messrs Ranbaxy Laboratories Limited, Okhla, New Delhi-110020 (DL/1546) (hereinafter referred to as the said establishmtnt) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible unde the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in Continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3658 dated the 19-7-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 24-9-1986 upto and inclusive of the 24-9-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one moth from the receipt of claim complete in all respects,

[No. S-35014/90/83-PF-II-SS-II]

का.आ. 329—मैसर्स प्रैशर कुकर एण्ड एपलियन्स लि., एफ-101, मेकर टावर, पो.ओ. बाक्स-16083, क्यूफी परेड, बम्बई और इसकी शाखाएं (एम.एच.-6333/इक्सन/27) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिये आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं से ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3710 तारीख 19-7-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 1-10-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिये जिसमें 30-9-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिये ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्दाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए, भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है तो जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा ।

8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/126/83-पी.एफ.-2/एस.एस.-2]

S.O. 329.—Whereas Messrs Pressure Cookers and Appliances Limited, F-101 Makers Towers, P.O. Box-16083, Cuffe Parade, Bombay including its branches (MH/6333/Exn/27) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. 3710 dated the 19-7-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 1-10-1986 upto and inclusive of the 30-9-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and manitain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/126/83-PF-II-SS-II]

का.आ. 330.—मैसर्स रिक्टि एंड कोलमैन ऑफ इंडिया लि., 41, चौरंघी रोड, कलकत्ता-700071 (डब्ल्यू. बी./1190) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कमचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कमचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3662 तारीख 19-7-1983 के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को, 24-9-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 23-9-1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्यक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना,

बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/विधिक वारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/94/83-पी.एफ2/एस.एस-2]

S.O. 330.—Whereas Messrs Rockit and Colman of India Limited, 41, Chowringhee Road, Calcutta-700071 (WB|1190) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 3662 dated the 19-7-1983 and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of three years with effect from 24-9-1986 upto and inclusive of the 23-9-1989.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional rovident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the payment of premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one moth from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/94/83-PF-II-SS-II]

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1987

का. आ. 331.—राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 क 34) की धारा 4 के खंड (घ) के अनुसरण में श्री बी. के. बरुआ के स्थान पर श्री बी. एम. हजारिका, सचिव, असम सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ० 545 (अ), दिनांक 25 जूलाई, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में, "(राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद 9 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :—

"श्री बी. एम. हजारिका,
सचिव, असम सरकार,
श्रम और रोजगार विभाग,
दिसपुर (असम)".

[संख्या यू-16012/7/85-एस. एस-1]

New Delhi, the 20th January, 1987

S.O. 331.—Whereas the State Government of Assam has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948) nominated Shri B. M. Hazarika, Secretary to the Government of Assam, Labour and Employment Department to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri B. K. Barooah,

Now, therefore in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, S.O. No. 545(E), dated the 25th July, 1985, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Government under clause (d) of section 4)", for the entry against Serial Number 9, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri B. M. Hazarika,
Secretary to the Government of Assam,
Labour and Employment Department,
Dispur (Assam)."

[No. U-16012/7/85-SS. I]

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1987

का. आ. 332—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91 के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2661, तारीख 30 जुलाई, 1984 के क्रम में, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के दाल मिल, लखनऊ के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन में पहली अक्तूबर, 1984 से 30 सितम्बर 1987 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए छूट देती है ।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्:—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शित किए जाएंगे ;

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते ;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे ।

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थीं ।

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी,—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं। जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तुरूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा:—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसे जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे, या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अभिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेजें, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे, या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है या वह कर्मचारी है, परीक्षा करना, या

(घ) ऐसे कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[सं. एस.-38014/39/86 एसएस-1]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि छूट के लिए आवेदन पत्र विलम्ब से प्राप्त हुआ था, किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 21st January, 1987

S.O. 332.—In exercise of the power conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. 2661 dated the 30th July, 1984, the Central Government hereby exempts the regular empoiyees of the Dal Mill, Lucknow belonging to the Food Corporation of India, New Delhi from the operation of the said Act for a period with effect from 1st October, 1984 upto and inclusive of the 30th September, 1987.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory,

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and

other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[F. No. S-38014/39/86-SS. I]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the application for exemption was received late. However it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1987

का. आ. 333.—मैसर्स जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, डीडवानोली, लास्कर, ग्वालियर–474001 (एम. पी./1092) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने सरकारी कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का 17) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है (की धारा 17 की उपधारा 2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा–2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनूसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3–क के खंड–क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ;

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अंतर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निदर्शितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर निश्चित करेगा।

[एस-35014(1)/87-एस. एस.-2]

New Delhi, the 21st January, 1987

S.O. 333.—Whereas Messrs Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadi, Deedwanaoli, Lashkar, Gwalior-474001 Madhya Pradesh) (MP|1092) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than thebenefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014(1)|87-SS-II]

का. आ. 334.—मेसर्स मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, एच. ओ. मल्टी स्टोरिड बिल्डिंग, टी. टी. नगर भोपाल, 462003 (एम. पी./1111) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा 2क) के अधीन छूट दिय जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का यथास्थिति मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाय, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्यक की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों तो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[एस-35014(2)/87-एस.एस.-2]

S.O. 334.—Whereas Messrs Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit, H.O. Multistoreyed Building, T. T. Nagar, Bhopal-462003 (MP/1111) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years ;

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall prrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been coverd under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employes of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee| legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects

[No. S. 35014(2)|87-SS-II]

का. आ. 335.—मैसर्स—अमरज्योति टेक्सटाईल प्रोसैसर्ज, 12 हैवी इन्डिस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर (राजस्थान) (आर. जे./3008) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम

के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[एस.-35014(3)/87-एस. एस.-2]

S.O. 335.—Whereas Messrs Amarjyoti Textile Processors, 12 Heavy Industrial Area, Jodhpur (Rajastran) (RJ|3008) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (17 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the empployees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(3)/87-SS-II]

का. आ. 336.—मैसर्स कालेखान मुहम्मद हनीफ, गुजराती बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। (एम.पी./2992) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा 2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों के एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाय, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014(4)/87-एस.एस-2]

S.O. 336.—Whereas Messrs Kale Khan Mohd. Hanif, Gujarati Bazar, Sagar (Madhya Pradesh) (MP|2992) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient fetures thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been coverd under the said Scheme, the employer shall pay the diffe ence to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees or the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowe to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee| legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014(4)|87-SS-II]

का. आ. 337:—मैसर्स न्यूटैक रिफैक्ट्रीज प्रा. लि., पोस्ट बाक्स नं. 63, 5-के.एम. अजमेर रोड, भीलवाड़ा (राजस्थान) (आर.जे./4164) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे

उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगी और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3क के खण्ड-क के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं. एस-35014(5)/87-एस.-एस-2]

S.O. 337.—Whereas Messrs Nutech Refractories Private Limited, Post Box No. 63, 5 K.M. Ajmer Road, Bhilwara, Pin Code-311001 (Rajasthan) (RJ|4164) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014(7)87-SS-II]

का. आ. 338.—मैसर्स सुखना पेपर मिल्ज लि., एस. सी. ओ.-116-117, सैक्टर 8-सी, मध्यमार्ग, चण्डीगढ़, (पी. एन./10325) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मासकीय समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा रोगियों का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होता तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं.-35014(6)/87-एम. एस.-2]

S.O. 338.—Whereas Messrs. Sukhna Paper Mills Limited, S. C. O. 116-117, Sector P-C, Madhya Marg, Chandigarh (PN|10325) (hereinafter referred to as the said establishment have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 19522) (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance, which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Chandigarh and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/ legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014(6)/87-SS-II]

का.आ. 339.—मैसर्स कुमार फैब्रिक्स (प्रा.) लि., 71/74 इन्डस्ट्रियल एरिया, दौहद रोड, बनसवारा-327001 (आर.जे./4083) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का 17 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) (की धारा 17 की उपधारा 2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप संहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा -2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 2-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का संपरीक्षण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उनके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा, निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते। बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय त्वरितता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[एस-35014 (7)/87-एस एस-2]

S.O. 339.—Whereas Messrs Kumar Fabrics Private Limited, 71|74 Industrial Area, Dohad Road, Banswara-327001 (RJ|4083) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Rajasthan and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S. 35014(7)|87-SS-II]

का.आ. 340.—मैसर्स सौराष्ट्रा केमिकल, पोरबन्दर-360576 (गुजरात) (जी.जे. 1367) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सबन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की इस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियम तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी का व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[एस-35014(8)/87-एस. एस. 2]

S.O. 340.—Whereas, Messrs Savrashtra Chemicals Porbandar-360576 (Gujarat) (GJ/1367) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), hereinafter referred to as the said Act).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Gujarat and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to effect adverselry the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Whereas, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(8)/87-SS-II]

का. आ. 341.—मैसर्स-महाराष्ट्रा एग्रो इन्डस्ट्रीज डिवेलपमेंट कार्पोरेशन लि., राजन हाऊस, तीसरी मंजिल, प्रभादेवी, बम्बई (एम. एच./11072) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 17) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा-2 क के अधीन छूट दिये जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदान या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा-2क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरिक्षक प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजन सामूहिक बीमा स्कीम

के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, बम्बई के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते । बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा। पर

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[एस.-35014(9)/87—एस.एस-2]

S.O. 341.—Whereas Messrs The Maharashtra Agro Industries Development Corporation Limited, Rajan House, 3rd Floor, Prabhadevi, Bombay (MH/11072) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014(9)/87-SS-II]

CORRIGENDUM

S.O. 342.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2727 dated 21st July, 1986, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated 2nd August, 1986, in line 1 after the word 'Mechanical' the word 'Works' shall be inserted.

[No. S-35014(201)/86-SS-II]

का. आ. 343.—गुजरात राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खंड (घ) के अनुसरण में श्री पी. वी. भट्ट के स्थान पर श्री एम. पी. पारेख, सचिव, गुजरात सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 545 (अ), दिनांक 25 जुलाई, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "[राज्य सरकार द्वारा धारा 4 के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]" शीर्षक के नीचे मद 11 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"श्री एम. पी. पारेख,
सचिव, गुजरात सरकार,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग,
न्यू सचिवालय, कम्पलेक्स, ब्लाक नं. 7, 7वीं मंजिल,
गांधीनगर ।"

[संख्या यू-16012/11/85-एस.एस.-I]

S.O. 343.—Whereas the State Government of Gujarat has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated M. P. Parekh, Secretary to the Government of Gujarat to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri P. V. Bhatt;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 545(E), dated the 25th July, 1985, namely :-

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Government under clause (d) of section 4)", for the entry against Serial Number 11 the following entry shall be substituted, namely :—

"*Shri M. P. Parekh*,
Secretary to the Government of Gujarat,
Health and Family Welfare Department,
New Sachivalaya Complex, Block No. 7,
7th Floor, Gujarat."

[No. U-16012/11/85-SS-I]

शुद्धि-पत्र

का. आ. 344.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 5 जनवरी, 1985 को प्रकाशित, भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) की अधिसूचना संख्या का. आ. 84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 के पृष्ठ 85 की पंक्ति 11-12 में —

"वीरापांडी" के लिए "वीरापांडी नंबर 4"
पढ़ा जाए ।

[संख्या एस-38013/23/84-एस.एस.-I]

CORRIGENDUM

S.O. 344.—In the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour), No. S.O 84, *dated 26th December*, 1984 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 5th January, 1985 at page-85 in line 12 for "Veerapandi" read "Veerapandi No. 4".

[No S. 38013(23)/84 SS.]

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1987

का. आ. 345.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध संबंधित स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं :—

1. मैसर्स बोनाफाइड एक्सपोर्टस, पटवा चैम्बर्स, पांचवीं मंजिल, मस्जिद स्टेशन के सामने दाना बन्दर बम्बई-9
2. मैसर्स माडल हाई स्कूल, कस्तूरबा नगर, वासीनाका, बम्बई-74
3. मैसर्स खादी ग्राम को-ओप्रेटिव कन्टीन लिमिटेड, 3 इरला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), बम्बई-56
4. मैसर्स दी पेपर रील्स कंपनी, बी-14 रायल इन्डस्ट्रीयल एस्टेट नया गांव क्रास रोड, वडाला, बम्बई-31
5. मैसर्स सैन्टरल इन्वेस्टीगेशन एंड सिक्युरिटी सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड, 160 डी. एन. रोड, प्रथम मंजिल, फोर्ट बम्बई-1
6. मैसर्स पी० जी० इलैक्ट्रोनिक्स 217 आशीर्वाद इन्डस्ट्रियल एस्टेट बिल्डिंग 3, राम मन्दिर रोड, गोरेगांव (पश्चिम), बम्बई-4

7. मैसर्स निप्पन कायजी कयोकाई, 105 मेकर चैम्बर्स-5 नारीमन प्वाइंट बम्बई-21

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त नियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[एस-35018(10)/86-एस. एस-2]

New Delhi, the 22nd January, 1987

S.O. 345.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. M/s. Bonafide Exporters. Patwa Chambers, opposite Masjid Station, Dana Bunder, Bombay-9.
2. M/s Model High School, Kasturba Nagar, Vasi-Naka, Bombay-74.
3. M/s. Khadigram Co-operative Canteen Limited, 3, Irla Road, Vile Parle (West), Bombay-56.
4. M/s. The Paper Reels Company, B-14, Royal Industrial Estate, 1st Floor Naigaum Cross Road, Wadala, Bombay-31.
5. M/s. Central Investigation and Security Services Private Limited, 160, D. N. Road, 1st Floor, Fort, Bombay-1.
6. M/s P. G. Electronics, 217, Ashirwad Industrial Estate. Building-3 Ram Mandir Road, Goregaon (West), Bombay-4.
7. M/s. Ninpon Kaiji Kyokai. 105, Maker Chambers National Highway, G. T. Road, Kundli. District

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35018(10)/86-SS-II]

का. आ. 346.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध संबंधित स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं :-

1. मैसर्स सुप्रीम एनेमल, 12/4 मथुरा रोड, फरीदाबाद
2. मैसर्स सीफाम औरगनिक्स लिमिटिड, 17 माइल स्टोन, नेशनल हाईवे जी. टी. रोड, कुंडली, जिला सोनीपत और इसका एम-134 द्वितीय खंड कैनाट सर्कस, नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय
3. मैसर्स पोलीइंक प्राईवेट लिमिटिड, 14/3 मथुरा रोड, फरीदाबाद और इसका आर-7ए ग्रीन पार्क, नई दिल्ली स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय
4. मैसर्स धारुहेरा कैमिकल्स, प्लाट नं. 3-4 धारुहेरा इंडस्ट्रियल एस्टेट धारुहेरा (महेन्द्रगढ) और इसका मुख्य 58 नेहरू प्लेस सहयोग भवन, नई दिल्ली-19 स्थित कार्यालय
5. मैसर्स सामन्ता प्राईवेट लिमिटिड, 11/7 मथुरा रोड, फरीदाबाद और इसका एन-146 पंचशील पार्क, नई दिल्ली स्थित रजिस्टर्ड कार्यालय
6. मैसर्स हरियाणा पैट्रो कैमिकल्स लिमिटिड, 55-59 हुडा इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-रिवाड़ी रोड, रिवाड़ी-1 और इसका 101-102 सूर्य मेनशन, 1, कौशल्या पार्क, हौज खास, नई दिल्ली-16 स्थित मुख्य कार्यालय

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त नियम की धारा 1, की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[एस-35019(187)/86-एस.एस-2]

S.O. 346.—Whereas it apepars to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. M/s. Supreme Enamels. 12/4, Mathura Road, Faridabad.
2. M/s. Cepham Organics Limited, 17th Milestone National Highway, G. T. Road, Kundli District Sonepat, including its Head Office at M-124, 2nd Floor, Connaught Circus, New Delhi.
3. M/s Polyink Private Limited. 14/3. Mathura Road, Faridabad, including its Registered Office at R-7A Green Park, New Delhi.
4. M/s. Dharuhera Chemicals Plot No. 3-4 Dharuhera Industrial Estate Dharuhera (Mahendergarh), including its Head Office at 58, Nehru Place, Sahyog Building, New Delhi-19.
5. M/s S: manta Private Limited. 11/7, Mathura Road, Faridabad, including its Registered Office at N-146, Panchsheel Park, New Delhi.
6. M/s. Haryana Petro-Chemicals Limited. 55—59 Huda Industrial Area, Delhi Rewari Road, Rewari-1, including its Head Office at 101-102 Surya Mansion, 1. Kaushalaya Park, Hauz Khas, New Delhi-16.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35019(187)/86-SS-II]

का. आ. 347:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध संबंधित स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं :-

1. मैसर्स भारत सर्विस स्टेशन, जी.टी. करनाल रोड, देहली करनाल बोर्डर, दिल्ली-40
2. मैसर्स स्पोर्ट्स अथार्टी आफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, लोदी रोड, नई दिल्ली
3. मैसर्स दी इंडियन सोसाइटी आफ इन्टरनेशनल लॉ, 7-8 सिन्धिया हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-1

4. मैसर्स पारस कंपनी, 33 डिप्टीगंज, दिल्ली–6 और इसकी सी–144 मायापुरी फेज–2, नई दिल्ली–64 स्थित फैक्ट्री।

5. मैसर्स इन्डो गल्फ फर्टीलाइजर्स एंड कैमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, तृतीय मंजिल होटल सिद्धार्थ कान्टीनेन्टल, बसंत विहार, नई दिल्ली–57 और इसकी लखनऊ (यू. पी.) स्थित शाखा।

6. मैसर्स बारबर शॉप ओबेराय इन्टर कान्टीनेन्टल, डाक्टर जाकिर हुसैन रोड, नई दिल्ली–3 और इसकी ब्रांच होटल ओबेराय शेरेटन, 15 ए, नारिमन प्वाइंट, बम्बई स्थित शाखा;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त नियम की धारा 1, की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[एस–35019(188)/86–एस.एस–2]

S.O. 347.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. M/s. Bharat Service Station, G. T. Karnal Road. Delhi Karnal Border, Delhi-40.
2. M/s. Sports Authority of India, Jawahar Lal Nehru Stadium, Lodi Road, New Delhi.
3. M/s. The Indian Society of International Law, 7-8 Scindia houst, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-1
4. M/s. Paras Company, 33, Deputy Ganj, Delhi-6 Including its Factory at C-144, Maya Puri, Phase-II. New Delhi-64.
5. M/s. Indo Gulf Fertilisers and Chemicals Corporation Limited, 3rd Floor Hotel Siddharth Continental, Vasant Vihar, New Delhi-57, including its Registered Office at Lucknow (U.P.).
6. M/s. Barbar Shop Oberoi Inter Continental, Dr. Zakir Hussain Road, New Delhi-3, including its branch at Hotel Oberoi Sheraton-15-A Nariman Point, Bombay.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35019(188)/86-SS-II]

का. आ. 348—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिएं :—

1. मैसर्स इलेक्ट्रो प्रोटेक्शन सर्विस नं. 59ए, कोटाए-युर रोड, कराएकुदी–2
2. मैसर्स थिलागाम आफसैट प्रिन्टर्स 9/4बी, पी. के. एस. ए. अरूमुगा नादर रोड, शिवकाशी
3. मैसर्स आर०बी० फाउंडरी, सी-12 एण्ड 13 प्राईवेट इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, कोयम्बतूर–21
4. मैसर्स कन्ता कलर 97, एन आर के आर स्ट्रीट, शिवकाशी–123
5. मैसर्स सेल्स सर्विस कम्पनी, 186 थाम्बू चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास–1
6. मैसर्स वीटा असफाल्ट्स एण्ड फैल्ट्स 62 ए (एन पी) सिडको इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, मद्रास–98 और इसकी मद्रास 101 स्थित शाखा
7. मैसर्स एस०वी०एन० सर्विसिज कारपोरेशन एस०वी० एन० हाउस नं. 90 सर सी. पी. रामास्वामी अय्यर रोड, मद्रास–18
8. मैसर्स श्री कुमार प्रिन्टिंग वर्क्स, 38 अरुणाचल अंसारी स्ट्रीट, सेलम–1
9. मैसर्स आयोनी फ्लूड बॉयलर इन्डिया लिमिटिड, चतुर्थ मंजिल 109 नुगामबाकाम, हाई रोड, मद्रास-34
10. मैसर्स दा मिन्नूर को-ऑपरेटिव मिल्स प्रोड्यूसर्स सोसाईटी लिमिटिड, मिन्नूर वानीयामबादी नार्थ आर्कोट कस्बा–7
11. मैसर्स श्री वानागामुदई ब्रिक्स वर्क्स संगामंगलम, मनामादुरई–13
12. मैसर्स वैंकटेशापेरुमल फाइनांसिंग कोरपोरेशन, 90 (नया नं. 207) डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद रोड, टाटाबाद कोयम्बतूर–12
13. मैसर्स इन्स्ट्रूमेंट्स एण्ड मशीन आई०एन०सी० 3 अरुमुगा निकट स्ट्रीट अन्ना रोड, मद्रास–2
14. मैसर्स पल्लवीराजा टैक्स पो. बा. नं. 131, 191 सेलम मेन रोड, कोमरापालायाम–183
15. मैसर्स एयर फ्रिग सर्विसेज, 167 पिटर्स रोड, मद्रास-14
16. मैसर्स फार्मस् एण्ड गियर्स एल–3 इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, गिन्डी, मद्रास–32
17. मैसर्स राजेश इन्डस्ट्रीज ओल्ड नं. 4/5 इनाया मुदाली स्ट्रीट नया नं. 97 कोरुकुपेट, मद्रास–21
18. मैसर्स पेक्को (इन्डिया लिमिटिड) 102 वेलाचेरी, रोड, गिंडी, मद्रास–32
19. मैसर्स लक्ष्मी सिल्क हाउस (मद्रास) एण्ड कम्पनी 10 प्रथम मंजिल नागेश्वरा राव रोड, मद्रास–17
20. मैसर्स सथानूर डैम गवर्नमैंट इम्पलाईज को-ओपरेटिव स्टोर्स लिमिटिड, एफ. एस. 372 सथानूर एस०ए० कस्बा
21. मैसर्स शुभ लक्ष्मी विविंग फैक्ट्री, 13वी, साउथ कालोनी पोस्ट बॉक्स नं. 171 कोमारापालायाम सेलम–183

22. मैसर्स रामा सिल्क फैक्ट्री नं. 228 मार्किट रोड, आरनी, नार्थ आर्काट कस्बा

23. मैसर्स मद्रास डाक लेबर बोर्ड इम्पलाईज को-आपरेटिव कैन्टीन लिमिटिड, राजा जी सलाए, एम डी एल बी बिल्डिंग, मद्रास–1

24. मैसर्स प्रेस्टिज रबर्स 136 आर्काट रोड, सालीग्रामम मद्रास–93

25. मैसर्स एमरल्ड इन्डस्ट्रीज प्लाट नं. 42 (एन पी) गिंडी डेवैलप्ड प्लाट, मद्रास 97 और इसका 32, 79 स्ट्रीट 18 एवेन्यू अशोक नगर, मद्रास 83 स्थित प्रशासनिक कार्यालय

26. मैसर्स कलाएमनी ग्राफिक्स मशीन (प्राईवेट) लिमिटिड, सिडको इन्डस्ट्रीयल स्टेट कुरूची कोम्बेतूर 21 और इसका ओपनाकारा स्ट्रीट, कोम्बेतूर –1 स्थित कार्यालय

27. मैसर्स सेलम कस्बा लारी ओनर्स एसोसिएशन 29 अय्यासामी चेती रोड सेवापेट, सेलम–2 और इसकी सेलम मेन रोड, सेलम 2 स्थित शाखा

28. मैसर्स श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फाईनान्स कम्पनी लिमिटिड रजिस्टर्ड कार्यालय 123 अंगप्पा निकेन स्ट्रीट, मद्रास–1 और इसका मद्रास स्थित प्रशासनिक कार्यालय तथा बंगलौर और सिकन्द्राबाद स्थित शाखाएं

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[एस 35019 (190)/86 एस. एस-2]

S.O. 348.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely:—

1. M/s. Electro Protection Services, No. 59A, Kattaiyur Road, Karaikudi-2.
2. M/s. Thilagam Offset Printers, 9/4-B, P.K.S.A. Arumuga Nadar Road, Sivakasi.
3. M/s. R. V. Foundry, C-12 and 13 Private Industrial Estate, Coimbatore-21.
4. M/s. Kanna Colours, 97, N.R.K.R. Street, Sivakasi-123.
5. M/s. Sales Service Company, 186, Thambu Chetty Street, Madras-1.
6. M/s. Beeta Asphalts and Falts, 62-A (N.P.) Sidco Industrial Estate Madras-98 including its branch at Madras-101.
7. M/s. S. V. N. Services Corporation, SVN House, No. 90, Sir C. P. Ramaswamy Iyer Road, Madras-18.
8. M/s. Sree Kumar Printing Works, 38, Arunachala Asari Street, Salem-1.
9. M/s. Ignifluid Boilers India Limited, 4th Floor, 109, Nungambakkam High Road, Madras-34.
10. M/s. The Minoor Co-operative Milk Producers Societies Limited, Minnoor Vaniyambadi TK. North Arcot District-7.
11. M/s. Sree Vanagamudi Bricks Works, Sangamangalam, Manamadurai-13.
12. M/s. Sree Venkatesa Perumal Financing Corporation, 90 (New No. 207) Dr. Rajendra Prasad Road, Tatabad, Coimbatore-12.
13. M/s. Instruments and Machines INC-3, Arumuga Naicken Street, Anna Road, Madras-2.
14. M/s. Patchiraja Tex, P.B. No. 131, 191, Salem Main Road, Komarapalayam-183.
15. M/s. Air Frig Services, 167, Peters Road, Madras-14.
16. M/s. Forms and Gears, L-3, Industrial Estates, Guindy, Madras-32.
17. M/s. Rajesh Industries Old No. 4/5, Ellaya Mudali St. New No. 97, Korukkupet, Madras-21.
18. M/s. Pebco (India) Limited, 102, Velacherry Road, Guindy, Madras-32.
19. M/s. Lakshmi Silk House (Madras) and Company 10, 1st Floor, Nageswara Rao Road, Madras-17.
20. M/s. Sathanur Dam Government Employees' Co-operative Stores Limited, H.H. 372, Sathanur Dam, N.A. District.
21. M/s. Subbulakshmi Weaving Factory-13-B, South Colony, Post Box No. 171, Komarapalayam, 183 Salem.
22. M/s. Ramma Silk Factory, No. 228, Market, Road Arni, North Arcot District.
23. M/s. Madras Dock Labour Board Employees Co-operative Canteen Limited, Rajaji Salai MDLB Building, Madras-1.
24. M/s. Prestige Rubbers, 136, Arcot Road, Saligramam, Madras-93.
25. M/s. Emerald Industries, Plot No. 42 (N.P.) Guindy Developed Plot, Madras-97, including its Administrative Office at 32, 79th Street, 18th Avenue, Ashoknagar, Madras-83.
26. M/s. Kalaimani Graphic Machine (Private) Limited, SIDCO Industrial Estate, Kurichi, Coimbatore-21, including its Office at Oppanakara Street, Coimbatore-1.
27. M/s. Salem District, Lorry Owners Association, 29, Avyasamy Chetty Road, Shavapet, Salem-2, including its branch at Salem Main Road, Salem-2.
28. M/s. Shriram Transport Finance Company Limited, Registered office 123 Angappa Naicken Street, Madras-1 including its administrative Office at Madras and branches at Bangalore and Secundrabad.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the abovementioned establishments.

[S. 35019(190)/86-SS-II]

का. आ. 349—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए:—

1. मैसर्स श्रीनिवासा राव एण्ड संस काकीनाडा ई. जी. कस्बा, आन्ध्र प्रदेश
2. मैसर्स श्री रघुराम मार्डन राईस मिल्स फोर्ट रोड, वारंगल

3. मैसर्स पी. वेंकट राव एण्ड सन्स, गजुलावेधि, विशाखापट्टनम
4. मैसर्स आदर्श एजेन्सी 7-1-26/1/1 अमीरपट्ट, हैदराबाद
5. मैसर्स कोस्टल रबड इन्डस्ट्रीज, 6/1, पटामाटा, विजयवाडा-6
6. मैसर्स संगम इन्जिनियरिंग टीम, 49-55-1ए, विद्युत नगर, विशाखापट्टनम-24
7. मैसर्स चिपिंग एण्ड पेंटिंग वर्कर्स सोसाईटी, डा० नं. 151, गांधीग्राम विशाखापट्टनम
8. मैसर्स विजया इन्जिनियरिंग कारपोरेशन, 47, डाक्टर कालोनी, विशाखापट्टनम-13
9. मैसर्स प्रसाद स्टील फैब्रीकेशन एन. एच-5 लंकाला-पालम, विशाखापट्टनम-21
10. मैसर्स श्री सरवाराया सुगर कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, नं. डी-1290, चेलरू, ई. जी. कस्बा
11. मैसर्स बाला रामा कृष्णा इन्जिनियरिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन 47-11-22, द्वारिका नगर, विशाखापट्टनम-16

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1 की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[एस-35019 (191)/86 एम. एस-2]

S.O. 349.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Empliyees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), shiuld be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. M/s. B. Srinivasa Rao and Sons ,Kakinada, E.G. Dt., A.P.
2. M/s. Sri Raghuram Modern Rice Mill, Fort Road, Warangal.
3. M/s. P. Vankat Rao and Sons, Gajulaveedhi, Visakhapatnam.
4. Ms. Adarsh Agencies, 7-1-26/1/1, Amcerpat, Hyderabad.
5. M/s. Coastal Rubber Industries, 6/1, Patamata, Vijayawada.
6. M/s. Sangam Engineering Team, 49-55-1A, Vidyut Nagar, Visakapatnam-24.
7. M/s. Chipping and Painting Workers Society, D. No. 151, Gandhigram, Visakhapatnam.
8. M/s. Vijaya Engineering Corporation, 48, Doctor's Colony, Visakhapatnam-13.
9. M/s. Prasad Steel Fabrications, N.H. 5 Lankalpalams, Visakhapatnam-21.
10. M/s. Sri Servaraya Sugar Co-operative Stores, Limited, No. D-1290, Chelluru E.G. District.
11. M/s. Bala Rama Krishna Engineering Construction Corporation, 47-11-22, Dwarakanagar, Visakhapatnam-16.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S-35019(191)/86-SS-II]

का. आ. 350.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पहली फरवरी, 1987 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 7 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध हरियाणा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"ग्राम सरसा हदबस्त नं. 2 और
ग्राम फुलपुरा हदबस्त नं. 3
तहसील और जिला भिवानी।"

[संख्या एस-38013/1/87-एस.एस-1]

S.O. 350.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st February, 1987 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Haryana, namely :—

"Village Sarsa Had Bast No. 2 and Village Phool Pura Had Bast No. 3 Tehsil and District Bhiwani."

[No. S-38013/1/87-SS-II]

का. आ. 351.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 फरवरी, 1987 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 (धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

क्षेत्र-ग्राम	होबली	तालुक	जिला
1. लग्गेरे	यशवन्तपुरा	बंगलौर उत्तर	बंगलौर
2. नल्लकदरनहाल्ली	यशवन्तपुरा	बंगलौर उत्तर	बंगलौर
3. चौक्कसन्द्रा	यशवन्तपुरा	बंगलौर उत्तर	बंगलौर
4. दसराहल्ली (टी. दसराहल्ली)	यशवन्तपुरा	बंगलौर उत्तर	बंगलौर

[संख्या एस-38013/3/87-एस.एस-1]

S.O. 351.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st February, 1987 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Karnataka, namely :—

Area village	Hobli	Taluk	District
1. Laggere	Yeshwantpura	Bangalore North	Bangalore
2. Nallakadaranahalli	Yeshwantpura	Bangalore North	Bangalore
3. Chokkasandra	Yeshwantpura	Bangalore North	Bangalore
4. Dasarahally (T. Dasarahally)	Yeshwantpura	Bangalore North	Bangalore

[No. S-38013/3/87-SS-I]

का. आ. 352.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किए जाने चाहिए :—

1. मैसर्स सीटीजन रबड़ एण्ड प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, 13 न्यू टांगरा रोड, कलकत्ता-46
2. मैसर्स रिजनल डायरेक्टर फुड एम्पलाईज को-ओपरेटिव कैन्टीन लिमिटिड, मोंगोलेन कलकत्ता-1
3. मैसर्स 'ए' टाइप टीफिन रूम इलक्ट्रोनिक्स क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोग शाला (पूर्व), इलैक्ट्रोनिक विभाग पी-1 तारा तोला रोड (प्रथम तल) कलकत्ता-88
4. मैसर्स आई०ए०एस० ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन, 10, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता-9
5. मैसर्स नार्दर्न कार्गो सर्विस, 20, बी०टी० रोड, कलकत्ता-2 और इसका 81, नीलगंज रोड, अगरपारा, 24-परगना स्थित गोदाम
6. मैसर्स धुप्पर सेल्ज ओरगनाइजेशन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटिड, 56/1, बिपलावी रास बिहारी बोस रोड (कैनिंग स्ट्रीट), कलकत्ता-1 और इसकी 1202, विक्रम टावर, 16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-8 स्थित शाखा
7. मैसर्स मिन्टस कारपोरेशन, 12 डा. बिरेश गुप्ता रोड, कलकत्ता-17 और इसका 5 क्लाइव रो कमरा नं. 20; ग्राउंड फ्लोर, कलकत्ता-1 स्थित कार्यालय
8. मैसर्स मल्टी केबल्स प्राईवेट लिमिटिड, 63 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता-40 और इसका 69-ए, प्रिंस बख्त्यार शाह रोड, कलकत्ता-33 स्थित प्रधान कार्यालय
9. मैसर्स पोजैक्टिव कमर्शियल कम्पनी लिमिटिड 6-ए, साकलात प्लेस, कलकत्ता-72 और इसकी कलकत्ता-13 तथा आमनसोल वर्दवान स्थित दो शाखाएं
10. मैसर्स कामरूप मेटल कारपोरेशन, 58/3 कनिंग स्ट्रीट (बिप्लावी रास बिहारी बोस रोड) कलकत्ता-1 और इसका जे० एन० मुकर्जी रोड, घुसरी, हावड़ा स्थित कार्यालय तथा जेल रोड, गोहाटी स्थित शाखा

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[एस-35017(12)/86-एस.एस-2]

S.O. 352.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely :—

1. M/s. Citizen Rubber and Plastic Industries, 13, New Tangra Road, Calcutta-46.
2. M/s. Regional Director Food Employees' Cooperative Canteen Limited, 4, Mango Lane, Calcutta-1.
3. M/s. 'A' Type Tiffin Room of Electronics Regional Test Laboratory (East), Department of Electronics Government of India, P-I, Taratoxla Road, (1st Floor) Calcutta-88.
4. M/s. I.A.S. Transport Corporation 10, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9.
5. M/s. Northern Cargo Service, 20, B.T. Road, Calcutta-2 including its Godown at 81, Nilgunj Road, Agarpara, 24-Parganas.
6. M/s. Dhupar Sales Organisation (India), Private Ltd., 56/1, Biplabi Rash Bihari Bose Road, (Canning Street), Calcutta-1 and its Branch at 1202, Vikram Tower, 16, Rajendra Place, New Delhi-8.
7. M/s. Mints Corporation, 12, Dr. Biresh Gupta Road, Calcutta-17 including its office at 5, Clive Row, Room No. 20, Ground Floor, Calcutta-I.
8. M/s. Multicables Pvt. Ltd., 63, Netaji Subhas Chandra Bose Road, Calcutta-40 including its head office at 69-A Prince Bakhtiar Shah Road, Calcutta-33.
9. M/s. Positive Commercial Co. Ltd., 6-A Saklat Place, Calcutta-72 including its Branches at (i) Calcutta-13 (ii) Asansoli, Burdwan.
10. M/s. Kamrup Metal Corporation 58/3, Canning Street, (Biplabi Rash Behari Bose Road), Calcutta-1 including its office at J. N. Mukherjee Road, Ghusuri Howrah and branch at Jail Road, Gauhati-1.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35017(12)/86-SS-II]

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1987

का. आ. 353.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापन से संबंद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध संबंधित स्थापन को लागू किये जाने चाहिए :—

1. मैसर्स स्टरलिंग प्लैटरस 14/1 सैक्टर-1, परवानो सोलन (पंजाब)
2. मैसर्स यूनको स्टील इंडस्ट्रीज (रजि.) होशियारपुर रोड, जालंधर
3. मैसर्स आटोमोटिव एजूकेशनल ट्रस्ट हिमाचल प्राइमरी स्कूल, सक्टर-1 परवानो, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट सोलन (हिमाचल प्रदेश)
4. मैसर्स जालंधर मोटर एजेंसी, नेहरू गार्डन रोड, जालंधर
5. मैसर्स मैक्स इंडिया लिमिटेड, ग्राम तोंन्सा, तहसील बालाचूर कस्बा होशियारपुर और इसकी 603/33 बी चंडीगढ़ और 72 नेहरू प्लेस, लक्ष्मी बिल्डिंग, तृतीय मंजिल, नई दिल्ली स्थित शाखाए

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1, की उप धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापनों को लागू करती है।

[एस-35019(189)/86-एस.एस-2]

New Delhi, the 22nd January, 1987

S.O. 353.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments, namely,

1. M|S. Sterling Platers, 14|1, Sector-1, Parwanoo, Solan (H.P.).
2. M|S. Unco Steel Industries(Registered) Hoshiarpur Raod, Jalandhar.
3. M|S. Automotive Educational Trust Himachal Primary School, Sector-1, Parwanoo, Tehsil and District Solan (H.P.).
4. M|S. Jalandhar Motor Agency, Nehru Garden Road, Jalandhar.
5. M|S. Max India Limited, Village Toansa, Tehsil Ballachur Dist. Hoshiarpur, including its branches at 603|33-B Chandigarh and 72, Nehru Place. Laxmi Building, 3rd Floor, New Delhi.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments.

[S. 35019(189)/86-SS-II]

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1987

का. आ. 354.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4317, तारीख 29 अगस्त, 1985 के क्रम में मैसर्स हिन्दुस्तान लेटेक्स पूजापुरा त्रिवेंद्रम को जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, प्रधान कार्यालय के नियमित कर्मचारियों को, उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अक्तूबर, 1985 से 30 सितम्बर, 1987 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है अवधि के लिए छूट देती है।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शित किए जाएंगे;

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही संदत्त किए, जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी,—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं;

या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा,—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखाबहियाँ और अन्य दस्तावेजें, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना।

[संख्या एस-38014/4/85-एस. एस-1]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के आवेदन पर कार्यवाही करने में समय लगा था। किंतु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 23rd January, 1987

S.O. 354.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91 A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 4317 dated the 29th August, 1985, the Central Government hereby exempts the regular employees of the Head office of M/s. Hindustan Latex Ltd, Poojapura, Trivandrum, a Government of India Undertaking from the operation of the said Act for a period with effect from 1st October, 1985 up to and inclusive of the 30th September, 1987.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of :—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be empowered to :—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[F. No. S-38014/4/85-HI (SSI)]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of any body adversely.

का. आ. 355.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91 के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य निगम के मक्का मिल प्लांट, फरीदाबाद, एक्स-यूनिट के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से पहले, मार्च, 1974 से दिसंबर, 1979 के 31वें दिन तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए छूट देती है।

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शित किए जाएंगे ;

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते ;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही संदत्त किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे ;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत था (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी,—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा,—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में के कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसी लेखाबहियों और अन्य दस्तावेजों, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसे जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे; या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना ।

[संख्या एस-38014/2/86-एस.एस-1]

ए. के. भट्टाचार्जी, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छूट के लिए आवेदन पत्र देरी से प्राप्त हुआ था । किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

S.O. 355.—In exercise of the power conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of the Maize Mill Plant, Faridabad, Ex-unit of the Food Corporation of India from the operation of the said Act for a period from 1st March, 1974 upto and inclusive of the 31st day of December, 1979.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and required any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[F. No. S-38019/2/86-SS-I]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the application for exemption was received late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of any body adversely.

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1987

का.आ. 356—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ब झान्जरा प्रोजेक्ट मैसर्स ई.सी.लि. के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार/औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-1-87 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 23rd January, 1987

S.O. 356.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jhanjra Project of M/s. Eastern Coalfields Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th January, 1987.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 57 of 1984

PARTIES :

Employers in relation to the management of Jhanjra Project of Eastern Coalfields Limited.

AND

Their Workmen

PRESENT :

Shri Justice Amitakh Dutta : Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of Employers : Shri N. Das, Advocate with Shri I. P. Singh, Personnel Manager.

On behalf of Workmen : Shri S. K. Acharya, Co-opted Executive Committee Member of the Union.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Coal.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by Order No. L-19012(35)/84-D-IV(B), dated 19th December, 1984 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication, namely :—

"Whether the action of the management of Jhanjra Project of Eastern Coalfields Limited, in dismissing Shri Rampat Harijan, Security Guard from service w.e.f. 30-1-1984 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?".

2. It appears from the record that the workman concerned was a Security Guard and was charged for serious misconduct under para 17(i) clause (a) of standing orders applicable to him as theft of certain articles of the employers worth about Rs. 5850/- took place while he was on duty.

3. Both parties have settled the dispute and settlement in writing signed on behalf of the parties has been filed today. The settlement is to the effect that the employer will reinstate the workman in his original job without payment of any back wages. The workman concerned will be given benefit of continuity of service for the period of his non-employment from the date of dismissal upto the date of his reinstatement and the workman will have no further claim against the employer whatsoever in regard to the industrial dispute covered by this reference.

4. Considering the circumstance of the case and the necessity of maintaining industrial peace and harmony in the establishment I find that the terms of the settlement appear to be fair and reasonable and should be accepted. An Award is passed in terms of the settlement between the parties which will form part of the Award as Annexure 'A'.

Dated : Calcutta,

The 6th January, 1987.

AMITABHA DUTTA, Presiding Officer

[No. I-19012/35/84-D. IV (B)]

R. K. GUPTA, Desk Officer

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 57 of 1984.

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Jhanjra Project of E.C.L.

AND

Represented by Colliery Mazdoor Union (INTUC), Cinema Road, P.O. Ukhra, Distt. Burdwan (W.B.)

The employer and the workmen jointly beg to state that the Industrial Dispute which is the subject matter of the above reference pending for adjudication by the Hon'ble Tribunal has been amicably settled between the parties on the following terms without however, admitting the correctness of the allegations made against each other leading to the Present Reference.

TERMS

1. That it has been agreed that the concerned workman Shri Ram Pat Harijan who had been dismissed from his service w.e.f. 30-1-1984 by the employer will be reinstated in his original job without payment of any back wages.

2. That the workman will be given the benefit of continuity of his service for the period of this non-employment from the date of his dismissal upto the date of his reinstatement.

3. That the workman will have no further claim against the employer whatsoever in regard to the industrial dispute covered in this reference and the parties will bear their respective cost of this reference.

1502 GI/86—10.

The parties, therefore, jointly pray that for maintaining Industrial peace and harmony at the establishment necessary order may kindly be passed permitting them to settle the dispute on the aforesaid terms and to pass an award accordingly by treating this petition as a part thereof.

Dated :

Sd/-

For Workmen

G. S. CMU (INTUC),

Cinema Road, Ukhra.

RAM PAT HARIJAN, Concerned Workman.

For & on behalf of Employer

General Manager,

Jhanjra Project.

Witness :

1. Indradeo Prasad Sah
2. Durga Mohan Chatterjee
3. Kisan Chatterjee.
4. Ramayan Singh.

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1987

का. आ. 357—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण बंगलौर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12 जनवरी, 1987 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 27th January, 1987

S.O. 357.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Bangalore, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Life Insurance Coporation of India, and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th January, 1987.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN KARNATAKA, BANGALORE

Dated this the 2nd day of January, 1987

Central Reference No. 3 of 1982

PRESENT :

Sri R. Ramakrishna, B.A., B.L., Presiding Officer.

I PARTY	Vs.	II PARTY.
Workmen represented by The LIC Employees' Union, Bangalore Division, No. 253, 9th Main Road, Sampangiramanagar, Bangalore-27.		The Senior Divisional Manager, L.I.C. of India, Divisional Office, Jeevanprakash Building, J.C. Road, Bangalore-2.

APPEARANCES :

For the I Party :—Sri M. C. Narasimhan, Advocate, Bangalore.

For the II Party :—Sri H. Shanmukhappa, Advocate, Bangalore.

REFERENCE

(Government Order No. L-17015(1)/81-D.IV(A) dated 27th February, 1982)

ORDERS on I.A. No. I

The Central Government has referred this matter for adjudication on the question that the workmen annexed to the points of dispute were eligible for appointment on regular basis and if so, whether the action of the management of L.I.C. of India in relation to Bangalore Division in not appointing the said workmen on regular basis is justified ? If not to what relief the concerned workmen are entitled ?

2. When this case has reached the stage of recording evidence the II Party have filed this application under Section 10(6) of the Industrial Dispute Act, 1947 to pass an order quashing the point of dispute in this refrenece on the ground that an identical order was referred to the National Industrial Tribunal at Bombay and the same was adjudicated on 17-4-86 by passing an award.

3. The grounds urged in the application, in brief, are that an industrial dispute in Reference No. NTB 1 of 1985 has been referred to the National Industrial Tribunal, Bombay on the following dispute :

> "What should be the wages and other conditions of sevice of Badli, Temporary and part-time workmen of Life Insuance Corporation of India as well as the conditions of their absorption in the regular course."

4. It is further contended that in view of the pendency of the above reference before the National Industrial Tribunal this Tribunal has no jurisdiction to adjudicate upon the points of dispute in this reference, as the points of dispute are similar and as such no parallel proceeding should continue and therefore this dispute automatically gets quashed under Section 10(6) of the Act.

5. The I Party has filed their objections contending thereon that Section 10(6) of the Industrial Disputes Act is not a procedural provision and does not enable a party to file such an application. Hence the same is liable to be rejected. It is further contended that as admitted by the II Party in para 6 of the application, it is not the same dispute but a similar dispute. A reading of Section 10(6)(a) of the I. D. Act will make it clear that unless the very dispute referred to the National Tribunal the proceeding pending before the Industrial Tribunal cannot cease. The Industrial Tribunal has no option but to proceed to pass an award as required under Section 15 of the Act. That the dispute that has been referred to this Tribunal has not been referred to the National Tribunal and the conseqnences of the said adjudication, reliefs to be granted are entirely different. It is further contended that the reference in NTB 1/85 is illegal and without jurisdiction as prior notice has not been given to the parties likely to be affected and the I Party Union is not made a party before the National Tribunal.

6. It is further contended that the dispute referred to the National Tribunal has to be a dispute which involves any quesion of National importance or is of such a nature that industrial establishments situated in more than one state are likely to be more interested in or affected by such dispute

7. It is further contended that the points of dispute referred by the same Government to the two Tribunals are not one and the same. This dispute relates to the specific claim of certain workmen whose names are mentioned in the Schedule to the Order of Reference. Such names are not mentioned in the reference to the National Tribunal. Secondly, the latter portion of the points of dispute in this reference refers to the non-appointment of the workmen on regular basis. In other words, the reference to this Tribunal includes the claim for reinstatement of the so-called badli workers at Bangalore office of the II Party and such a matter has no been referred to the National Tribunal. It is also impossible for the said dispute to fall within the category of dispute that alone to be referred to the National Tribunal under Section 10(1) of the Industrial Disputes Act. Such a purely local issue cannot be referred to the National Tribunal. This would mean that either the reference to the National Tribunal is invalid or alternatively this would mean that the order of reference concerned should be so construed as to avoid a conflict. It is further contended that the above complex issues cannot be decided without closely examined all the relevant documents, namely, the order of reference in the two cases, the pleadings of the parties and the issues framed in both the cases. Unless circumstances leading to the reference to the National Tribunal are known in detail it would not be possible to decide the application at all. Without the Central Government being made a party, this application cannot be disposed of. Hence I.A. 1 deserves to be rejected.

8. Now the points that arise for determination are :

(1) Whether the points of dispute referred for adjudication to the National Industrial Tibunal are similar to the points of dispute pending before this Tribunal for adjudication ?

(2) If the above point is held in the affirmative whether the present dipute is hit by Sec. 10(6) of the Industrial Disputes Act ?

(3) What order ?

9. Findings :

Point No. 1 :—Affirmative
Point No. 2 :—Affirmative.
Point No. 3 :—As per order below :

10. Findings :

Point No. 1 :—When I.A. No. I was filed the reference made to the National Industrial Tribunal was pending adjudication Since the I Party has contended in their objection statement the necessity of the reference, the pleadings are required to give a finding on this application. The II Party have furnished the copies of these materials and also the award made by the National Industrial Tribunal and published in the Gazette of India on 17-6-1986.

11. The points of dispute referred to this Tribunal are as follows :—

> "Whether the workman of Life Insurance Corporaiton of India, Bangalore Division, mentioned in the annexure were eligible for appointment on regular basis ? If so, whether the action of the management of Life Insurance Corporation of India in relation to Bangalore Division in not appointing the said workmen on regular basis is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

12. On the basis of this point of dispute the I Party—Union have contended in their claim statement that the name of employees shown in the points of dispute that the Corporation is extracting work from these employees giving different nomenclature as coolies or part timers, watchmen in order to deprive them of the confirmation and other benefits of subordinate staff. They sought for regularising the services of all these employees as full time employees extending all the benefits that has been enjoyed by permanent employees.

13. The point of dispute referred to the National Industrial Tribunal is as follows :—

> "What should be the wages and other conditions of service of Badli, temporary and part-time workmen of Life Insurance Corporation of India as well as the conditions of their absorption in the regular cadre ?"

14. On a reading of the points of dispute referred to this Tribunal and to the National Industrial Tribunal the reference made to the latter is more exhaustive than the reference made to this Tribunal, as the latter reference includes the Badli and Temporary workmen.

15. In the counter statement filed before this Tribunal by the II Party it is contended under Section 23(1) of the Life Insurance Corporation Act, shortly called Act, the Corporation is empowered to employ such number of persons to discharge its functions. Under Section 48 of the said Act, the

Central Government may by notification make rules to carry out the purpose of the said Act. Under Section 49 of the Act, the Corporation may with the previous approval of the Central Government by notification in the Gazette of India make Regulations not inconsistent with the Act and the Rules, to provide for all matters for which provision is expedient for the purpose of giving effect to the provisions of the Act. It is further contended that since the power to make rules and regulations has been taken over by the Government of India, the Regulations and Rules in force prior to the amendment are deemed to be the rules made in the Amendment Act 1981. The Corporation has to strictly follow the rules and it cannot deviate or modify the said rules. The appointment of Class III and IV employees are made and governed by the Life Insurance Corporation of India instructions of 1979. These instructions were issued by Chairman in exercise of the powers vested on him under Regulation 4 of the Staff Regulations. The recruitment and appointments are made in accordance with the instructions of the Central Government by calling for applications through Employment Exchange.

16. They have further contended that the persons whose names are mentioned in the annexure to the reference were being engaged only as casual labourers and temporary on day to day basis. The duration of engagement is also for a very short period and with break. They are not at all eligible for appointment on regular basis either under the L.I.C. Recruitment instructions 1979 or any other law, and they have already recruited some of the workmen shown in the points of dispute on permanent basis and part time basis.

17. Before the National Industrial Tribunal after the reference has been made the preamble of the order pointed out "that the dispute is in such a nature that establishment of L.I.C. situated in more than one state are likely to be interested in or affected by such dispute the reference has been made to the National Industrial Tribunal to adjudicate the dispute."

18. The National Industrial Tribunal after the reference has been made, has impleaded six other unions of the Corporation, as in the reference order there were only two unions joined as parties viz., Western Zone Insurance Employees Association, Bombay and Central Zone National Life Insurance Corporation Employees' Association, Kanpur. All these eight unions represeing the workmen of the above categories have filed their claim statements in support of their demands. In the claim statement by one of the unions viz., All India Insurance Employees Association Calcutta. The case of badli, temporary and part time workmen was dealt with exhaustively from para 22 to para 44.

19. The Corporation in their written statement before the National Industrial Tribunal has taken up the same contentions similar to the contentions taken in this dispute and also absorption of temporary employees on a permanent basis as and when the vacancies are occured or sanctioned posts were available for filling up.

20. On a reading of the points of dispute and the contenions urged by both parties are found to be similar in both the disputes. Hence I find no merit in the submission of the learned counsel for the union that the points of dispute referred this Tribunal and to the National Industrial Tribunal are different, except to the extent that the reference made to the National Tribunal is subsequent to the reference made to this Tribunal. In view of this, the 1st joint is held in the affirmative.

21. Point No. 2:—The learned counsel for the Corporation has submitted that the issue now pending before his Tribunal was also a point referred to the National Tribunal and since an adiudication is made by an award which is binding on all the workmen of Corporation throughout India, the reference now pending before this Tribunal is hit by Section 10(6) of the Industrial Disputes and the reference is liable to be quashed. The learned counsel further submitted that in view of the award made by the National Tribunal the local L.I.C. taken the step to absorb and regularise the eligible candidates and any independent award by this Tribunal will likely affect and prejudice the interest of the workmen who are eligible or regularisation at present. The learned counsel further submitted that if a finding is given different to that of a finding already given by the National Industrial Tribunal, the said finding is likely to disrupt and dishormony the structure of the Corporation which is being done on all India level basis. Against this submission, the learned counsel for the I Party union submitted that if it is the contention of Government of India to treat that the reference made to the National Industrial Tribunal cover the poin's of dispute pending before this Tribunal they should have sent a copy of the reference and a notice to this Tribunal and even in the written statement filed by the Corporation before the National Industrial Tribunal this fact is not disclosed, hence section 10 (6) has no application to the present reference.

2 On a perusal of the award made by the National Industrial Tribunal, Bombay, the learned Presiding Officer has givent a broad out-line of the dispute that requires adjudication in para 3 of the award as follows :—

> "It would be convient to divide this dispute into two parts, one relating to wages and other conditions of service and the other with regard to their absorption in regular cadre. It is also necessary, in order to define to describe what are the kinds of employees covered in the employment, which occurs in their case who are generally described in the reference as badli, temporary and part-time workmen. Admittedly, these categeries of employees belong to class-III and cass-IV. Even in between then it is common ground that there are no class-III employees in the part-ime group of category of employees, who are covered in this reference. There are also no badli employees from Class-III. In other-words, therefore, of the three kinds of employees covered by this reference, class-III employees only belong to temporary category while the class-IV category employees belong to all the three groups, namely, badli, temporary and part-time".

23. Section 10 (6) of the Industrial Disputes Act reads as follows :—

> "Where any reference has been made under sub-section (IA) to national Tribunal, then notwithstanding anything contained in this Act, no Labour Court or Tribunal shall have jurisdiction to adjudicate upon any matter which is under adjudication before the National Tribunal, and accordingly :—
>
> (a) if the matter under adjudication before the National Tribunal is pending in a proceeding before a Labour Court or the Tribunal, as the case the Labour Court or the Tribunal, as the case may be, in so ar as it relates to such matter, shall be deemed to have been quashed on such reference to the National Tribunal; and
>
> (b) It shall not be lawful for the appropriate Government to refer the matter under adjudication before the National Tribunal to any Labour Court or Tribunal for adjudication during the pendency of the proceeding in relation to such matter before the National Tribunal."
>
> "Explanation.—In this sub-section, Labour Court, or Tribunal includes any Court or Tribunal or other authority constituted under any law relating to investigation and settlement of industrial disputes in force in any State".

24. On a plain reading of Section 10 (6) it has been devised for avoiding multiplicity of proceedings which may result from such a reference. The effect of non-obstatute clause is that irrespective of the other provisions in the Act, it is the National Tribunal alone which will be seized of the matter referred to it after a reference under sub-section (IA), to the complete exclusion of adjudication by other adjudicatory authorities either under this Act or under any State statute. the combined effect of the provisions (a) and (b) under Section 10 (6) is not merely to impose a prohibition against proceeding with the enquiry before the Tribunal, but there

is a obligation cast on the Tribunal to treat, the proceedings which would include the reference itself, as void as having been quashed by the reference to the National Tribunal.

25. This Tribunal after perusing the award made by the National Tribunal is satisfied that the points of dispute made before this Tribunal is already adjudicated exhaustively by the National Tribunal, the reference stands quashed and further adjudication is found unnecessary. Hence I hold this point also in the affirmative.

26. Point No. 3 :—In the result, the reference made to this Tribunal fails and the same is hereby rejected without expressing any opinion on the merit of this reference.

(Dictated to the Stenographer, transcribed and typed by him and corrected by me).

R. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

[No. L-17015/1/81-D IV (A)]

K. I. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1987

का.आ. 358 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, डीविजनल रेलवे मैनेजर वैस्टर्न रेलवे, कोटा के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13 जनवरी, 1987 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 29th January, 1987

S.O. 358.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of D.R.M., Western Railway, Kota, and their workmen, which was received by the Central Government on the 13-1-87.

BEFORE SHRI G. S. KALRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 75/78

In the matter of dispute between :

Shri Inder Parkash and Others (through Divisional Secretary, Paschim Railway Karamchari Parishad, in front of Hasthal, Bhimganj Mandi, Kota-2 (Raj.)

Versus

1. Divisional Railway Manager, Western Railway, Kota.

2. The General Manager, Western Railway, Churchgate, Bombay.

APPEARANCES :

Shri A. D. Grover—for workmen

Shri V. P. Mishra—for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its notification No. L-41011(9)/77-D.II(B) dated 17th August, 1978 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

I. Whether the action of Divisional Superintendent, Western Railway, Kota in treating the Bungalow Peons in separate cadre and thereby retrenching the senior Hamals whose names are mentioned below vide notice dated the 21st April, 1977, is justified? If not, to what relief are these Hamals entitled?

Names of Hamals

(1) Shri Inder Prakash.

(2) Shri Baboo M.

(3) Shri Chotey Lal.

(4) Shri Ashok Kumar M.

(5) Shri Ganpat H.

(6) Shri Narain Singh.

(7) Shri Prakash.

II. Whether the action of the Divisional Personnel Officer, Western Railway, Kota in terminating the services of the undermentioned casual workmen under the Inspector of Works (W&D), Western Railway, Kota with effect from the 23rd April, 1977 is justified? If not, to what relief are these workmen entitled?

Names of the Casual workmen

(1) Shri Hardeo Singh, son of Shri Kanahiya Lal.

(2) Shri Roop Singh, son of Shri Sarkara Bhai.

(3) Shri Ramdeo, son of Shri Mangilal.

(4) Shri Amarlal, son of Shri Daulat Ram.

(5) Shri Satyanarain, son of Shri Damodar.

(6) Shri Ravilal, son of Shri Kanahiya Lal.

(7) Shri Brij Kishor, son of Shri Surajnarain.

(8) Shri Kamlesh Chandra, son of Shri Suraj Prasad.

III Whether the action of the Divisional Superintendent, Western Railway, Kota in not paying wages at higher rates to the undermentioned employees after completion of 6 months service under the Permanent Way Inspector, Bharatpur is justified? If not, to what relief are they entitled?

Names of the employees

(1) Shri Shyamlal S.

(2) Shri Soni.

(3) Shri Sadar Khunni.

(4) Shri Bhagwan Singh M.

(5) Shri Amar Singh M.

(6) Shri Paras Ram R.

(7) Shri Gyasi S.

(8) Shri Sukhchandi L.

(9) Shri Kirori K.

(10) Shri Ram Lal D.

(11) Shri Nathi Permoli."

2. The case of the workmen as setforth in the statement of claim schedule-wise is as under :

Schedule No. 1

The applicants were working as substitute Hamals in the office of the Divisional Superintendent, Western Railway Kota and they were served with retrenchment notice dated 21-4-77 mentioning the reason that their services were no more required because of the less absentees of Class IV staff. However, the reasons given for retrenchment were absolutely incorrect as juniors to the claimants viz. S|Shri Ismail s/o Abdul, Abdul Hamid s/o Ibrahim, Baloo II and Dal Chand were continued in service. No seniority list was displayed nor the principle of last come first go was followed and thus there has been violation of Rules 76 and 77 of the I.D. Act Central Rules 1957 and Section 25-H of

the I.D. Act. Hence the termination of the services of the not paid the retrenchment compensation at the time of their retrenchment and thus there is violation of Section 25-F of the I.D. Act. Hence the termination of the services of the claimants is illegal and liable to be set aside.

Schedule No. II

The workmen listed in this schedule were working under I.O.W. (W&D) Western Railway, Kota. It is alleged that artificial breaks were made in their service to deprive them of their legitimate rights of becoming Railway Servants. These workmen were retrenched w.e.f. 23-4-77 and re-engaged on 29-4-77. No notice was served nor any notice-pay in lieu of notice and retrenchment compensation was paid. Hence retrenchment of these workmen is illegal and liable to be set aside.

Schedule III

It is stated that the workmen have worked as casual gangmen under PWI Bharatpur for the period shown against each of them as under :

(1) Shri Shyam Lal S. Gang No. 112	1960 to 1969
(2) Shri Soni Gang No. 112	1963 to 1968
(3) Shri Sardar Kaluram Gang No. 112	1963 to 1968
(4) Shri Bhagwan Singh M. Gang No. 112-B	1961 to 1968
(5) Shri Amar Singh M 112	1962 to 1968
(6) Puraram R 112	1963 to 1968
(7) Shri Gyasi I 112-B	1963 to 1969
(8) Shri Sukhchandi I 112	1963 to 1971
(9) Shri Kirori K. 112-A	1963 to 1969
(10) Shri Ram Lal D. 112	1963 to 1973
(11) Shri Nathi Parmoli 112	1963 to 1967

As per the Extant Rules they ought to have been paid authorised scale of pay after completion of six months service but they have not been so paid and hence it was prayed that the Management be directed to make payment as pper authorised scale together with the arrears.

3. The reply of the Management Schedule-wise is as under :

Schedule No. I

It is admitted that the claimants had been working as Hamals in the Office of the Divisional Superintendent, Western Railway, Kota and that they were served with retrenchment notice but it was denied that juniors were retained in service and the principle of last come first go was not followed. It was also denied that the termination of services of these claimants is illegal and the claimants were called upon to specify the names and designations of the employees who were alleged to have been retained in service although they were junior to the applicants.

Schedule No. II

The notice of termination of the workmen-claimants was revoked and the period from 23-4-77 to 29-4-77 was treated on duty and the claimants have been paid their wages and at present the applicants are working as casual labour in authorised scale.

Schedule No. III

The Railway Administration had never denied to pay the arrears of authorised scale and this work being voluminous required sufficient time and the arrears will be paid as per rules.

4. The workmen in their rejoinders furnished the names of the juniors who were retained in service as under :

1. Shri Ismail S/o Shri Abdul working as peon in Control Office Divisional Suptd. Western Railway Office, Kota-2.
2. Shri Abdul Hanif S/o Ibrahim working as a Khalasi in C&W Depot, Western Railway, Kota.
3. Shri Baloo H. working as bunglow Peon in APO's house.
4. Shri Dal Chand working as Peon of Divisional Mechanical Engineer (C&W), Kota.

5. My findings schedule-wise are as under :

Schedule No. I

The workmen in their statement of claim itself had mentioned the names of four junior employees who were retained in service and, therefore, the contention of the management in the written statement that the workmen should specify the names and designations of the employees who were retained in service though they were juniors is quite illogical. In any case the workmen have provided further detailed particulars of these workmen mentioning the place of their employment in the rejoinder filed by them and which have been reproduced above. However, all that the Management had to say through Shri K. P. Saxena Chief Clerk in the Office of the DRM Kota is that the names of person given in the rejoinder are not relevant to this case as one out of those 4 i.e. Baloo-H was utilised as Bungfow Peon and the rest three were not employed in the Unit where the claimants were employed. This averment of Shri K. P. Saxena appears to be incorrect on the face of it because it has been mentioned in the rejoinder that Shri Ismail s/o Abdul was working as Peon in the office under the Control of Divisional Superintendent, Western Railway, Kota and the contention of the workmen-claimants in their statement of claim is also that they were working in the office of the Divisional Superintendent Western Railway Kota. Hence it is quite inexplicable as to how the Management can say that the three persons other than Baloo H mentioned in the rejoinder were not employed in the same Unit as the claimants. Now Shri K. P. Saxena in his cross-examination when he appeared in court first stated that the seniority of casual employees for retrenchment is unitwise and not division-wise. Later he stated that the entire class IV staff of Divisional Office is one cadre. He further stated that Hamals, Bunglow Peons and other Peons are all in one cadre. If the entire class IV staff of the Divisional Office constitute one cadre and the Hamalas, Bunglow Peon and other peons are all in one cadre, the four workmen mentioned in the statement of claim as well as the rejoinder would therefore be in the same cadre as the claimants. As the Control Office of the Divisional Superintendent C&W Depot Divisional Mechanical Engineer C&W, all fall within the Kota Division of the Western Railway, this statement of Shri K. P. Saxena MW1 virtually admits the claim of the workmen and negates the stand of the Management taken before the appropriate government which necessitating the reference of this dispute. As all the class IV staff include Hamals, Bunglow Peons and other peons admittedly constitute one cadre, there was no justification for the Management to treat the Bunglow Peons separately from the Hamals and other peons and thereby to have retained in service junior employees and retrenched the claimants who were senior to them. There is a clear violation of the principle of last come first go in the case of these workmen and hence action of the Management cannot be justified. The Ld. representative for the Management has tried to draw some succour from the letter dated 5-12-68 addressed by the Head Quarters office of the Western Railway to the Divisional Superintendent in which some instructions regarding appointment of Bunglow Peons were issued. However, even this letter makes it clear that the appointment of bungalow peons is normally made from the peons working in the office but if the concerned officer does not like to appoint an office peon as his bunglow peon, he can select a candidate of his own choice, only if there are vacancies and the officer concerned would exercise this option only once so as to avoid this being a method of irregular recruitment to class IV posts. It is therefore, clear that this letter gives some relaxation in the procedure for recruitment but it does not say anything about the retrenchment of class IV employees. In other words an officer entitled to Bungalow Peon can select a person other

than peons working in the office only if there are vacancies, which would mean that the person so selected would be placed junior to the persons already working as office peons and in case of retrenchment he will have to go by principle of last come first go, if there is no vacancy. Hence the action of the Management is not at all justified. Therefore, the claimants are entitled to reinstatement with continuity of service and with back wages subject to the availability of vancancies available on the date of termination as per the common seniority of the class IV employees of the Kota Division of the Western Railway including Hamals and Bunglow Peons.

Schedule No. II

All the workmen have since been reinstated and the period between the termination and reinstatement treated as on duty, and they have been paid their wages for this period. Hence these claimants have got no further grievance.

Schedule No. III

The Management has conceded that on completion of six months service the workmen are entitled to the authorised scale of pay. However, the reasons given for non-payment viz. the work being voluminous and required time, is not sufficient justification for the inordinate delay in making the payment. It is, therefore, directed that the Management should make the payment of the arrears within one month of the date of enforcement of the award alongwith 12 percent interest w.e.f. 17-8-78 when the reference was made by the Appropriate Government.

6. This reference stands disposed of accordingly.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

18th December, 1986.

G. S. KALRA, Presiding Officer
[No. L-41011/9/77-D.II(B)(Pt.)]
HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1987

का.आ. 359 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, उत्तर रेलवे बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली, के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-1-87 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 29th January, 1987

S.O. 359.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway, Baroda House, New Delhi and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th January, 1987.

BEFORE SHRI G. S. KALRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 31/83.

In the matter of dispute between :

Shri Bhagwan Singh, s/o Shri Shiv Lal, r/o 248, Khanpur, New Delhi.

Versus

General Manager, Northern Railway, New Delhi

APPEARANCES :

Shri Bhawan Singh workman in person.

Shri S. L. Nim for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its notification No. L-41012(10)/80-D. II(B) dated 15-3-82 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the management of Northern Railway, Baroda House, New Delhi is justified in terminating employment of Shri Bhagwan Singh, Khalasi beyond 14th October, 1978. If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The workman in his statement of claim has stated that he joined the service of the respondent as casual khalasi w.e.f. 28-5-76 and he had completed more than 870 days of work without any break and in view of his long spell of service he got the status of permananet worker. A test was conducted by the Management for absorption of Khalasis on permanent basis and he qualified in that test but was never made permanent whereas the other workmen who were junior to the workman were made permanent. The Management terminated the service of the workman without assigning any reason which action was illegal and contrary to the provisions of law and principles of Natural Justice. His termination amounted to retrenchment but no retrenchment compensation was paid hence there is violation of section 25 of the I. D. Act. Hence the workman has prayed that he may be reinstated in service with continuity of service and full back wages.

3. The Management in its written statement pleaded that the claimant was an unwilling worker and had been served with letter asking his explanation for misbehaviour and disobedience to carry out instructions to perform duty but instead of submitting any reply he left the employment and never returned thereafter to report for work. It was denied that the applicant had acquired permanent status before he deserted his service. It was further stated that although the claimant had qualified the screening test for appointment as Khalasi his number in the list was at serial No. 190. It was denied that any junior person to him in the list was issued medical memo for absorption as Khalasi prior to the date he left the employment. The service of the claimant was as a casual worker and his services were never terminated as alleged but he himself left the work of his own accord. There has been no termination of service or retrenchment as the claimant left the work of his won accord and hence he is not entitled to the protection of section 25-F or any other relief.

4. The short question that arises for determination in this case is whether the services of the workman were terminated on 14-10-78 as alleged by the workman or whether it is a case of abandonment of services by the claimant as alleged by the Management. Although the record of service as casual labour Ex. WZ-1 shows the last date of working of the claimant as 14-7-78 yet the Management has produced sufficient evidence which goes to prove that the claimant had actually performed duty upto 31-3-79 This is evidenced from the document Ex. MZ-1 which contains the details of working days of the claimant right from 15-7-76 to 31-7-1979 It goes to show that the claimant had put in duty for 143 more days after 14-10-78. The similar position is forthcoming from the letter Ex. M-1 dated 11-9-1981 addressed by the Divisional Personal Officer, New Delhi to the General Manager (P) Northern Railway, Baroda House, New Delhi in which it was clearly stated that the claimant-workman had left his service of his own accord and that the claimant's claim that his services were terminated w.e.f. 15-10-78 is not correct, since he was engaged subsequently as was clear from his service particulars. The reference to this Tribunal was made vide order dated 15-3-1982. Therefore, the letter Ex. M-1 which though written in connection with the industrial dispute yet was written prior to the order of reference and, therefore, it appears to be authentic. It has been reiterated by MW1 Shri Rajiv Bhatnagar also that the claimant worked upto 31-3-79 and that after 31-3-79 he did not come and left of his own accord. He has further stated that on 29-3-79 an FIR was lodged against him for his misbehaviour with I.O.W. Nizamuddin and that is why he did not come after

31-3-79. The workman has not been able to produce any evidence which could go to prove that his services were terminated on 14-10-78 or that he had not performed any duty upto 31-3-79 as alleged by the Management. It is pertinent to mention here that the service card Ex WW-1 was in the custody of the workman and he was getting periods of his work authenticated from time to time. It further appears that he did not get any entry made for the period after 14-10-78 and he has tried to take undue advantage of the non-existence any entry of his service beyond 14-10-78 in the Service Card by alleging that his services were terminated on 14-10-78. The evidence produced by the Management goes to prove that the workman is guilty of making a false statement that his services were terminated on 14-10-78 because he is proved to have actually worked with the Management upto 31-3-79. Since the workman is proved to have been performing the duty with the respondent upto 31-3-79, the question of termination of service of the workman on 14-10-78 does not arise. In the circumstances, the contention of the Management that the workman himself abandoned his service and that it was not a case of termination appears to be correct and is accepted. Hence the workman is not entitled to any relief and this reference stands disposed of accordingly.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

31st December, 1986.

G. S. KALRA, Presiding Officer

[No. L-41012|10|80-D. II(B)]

HARI SINGH, Desk Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987